Follow us on :
bharatbhaskar.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
भारत भास्कर
हर खबर का असर
डाक पंजीयन - छ.ग. / रायपुर संभाग / 58 / 2021-2023
● वर्ष : 16 ● अंक-191 ● रायपुर, मंगलवार 06 अगस्त 2024 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य-2 रूपये ● रायपुर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ एवं दिल्ली से प्रकाशित ● RNI-CHHHIN/2009/29179

सूर्योदय 6.22
सूर्यास्त 5.38
श्रावण शुक्ल
पक्ष-द्वितीया

सुविचार

हौसलों से कुछ नहीं होता, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य भी करना पड़ता है।
- स्वदेश तिवारी

एनटीपीसी लारा ने सहयोगी गांवों की महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया 3

जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, हटाए गए समन्वयक विनोद गुप्ता 5

छ.ग. श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का जिला स्तरीय बैठक संपन्न 7

डीएमएफ फंड से अवैध प्लॉटिंग में हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर एक महीने बाद भी नहीं हुई कार्यवाही...

क्या मामला दबाने हो रही प्लानिंग...? पीडब्ल्यूडी को जांच का जिम्मा... पर जांच का अतापता नहीं...

उपयोगिता, पूर्णता प्रमाण पत्र में 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर... जनपद CEO, RES SDO और इंजीनियर भी कटघरे में...

मुंगेली/ भ्रष्टाचार के लिए मुंगेली जिले की पहचान प्रदेश में अलग ही हैं, मुंगेली भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के लिए प्रसिद्ध हो चुका हैं, कई विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर आये दिन शिकायत होते रहते हैं जो समाचारों की भी सुर्खियां बनी रहती हैं।

हाल ही में मुंगेली जिले में डीएमएफमद से नगर पालिका क्षेत्र के अवैध कालोनी में हुए सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला, मुंगेली जिले के खनिज न्यास फंड (डीएमएफ) के खर्च को लेकर अफसरों की मनमानी का मामला सामने आया है। फंड के पैसों का दुरुपयोग कर मनचाहे जगह पर उपयोग किया गया, जो कि नियम विरुद्ध हैं। पहले भी इस बात का उल्लेख किया जा चुका हैं।

आपको बता दे कि मुंगेली जिले के एक ग्राम पंचायत ने नगर पालिका क्षेत्र के अवैध कालोनी में डीएमएफ मद से करीब 14.98 लाख रुपये का सड़क निर्माण किया हैं, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया और यह सड़क 2-3 माह में ही पूरी तरह जर्जर हो गया। जिससे इस सड़क निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हैं। कालोनीवासियों ने बताया कि नगर पालिका, अवैध कालोनी हैं कहकर सड़क नाली नहीं बना रही थी, बड़ी मुश्किल से जब यह सड़क डीएमएफमद से बना तो यह भी 2-3 महीने में उखड़कर जर्जर हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता हैं कि अगर इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया तो इसकी सतत निगरानी और गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई और निगरानी की गई तो किसके द्वारा की गई ? किसकी जवाबदेही थी ? क्षेत्रवासियों का कहना हैं कि यदि जनता की सुविधा के लिए डीएमएफमद से सड़क निर्माण किया गया तो सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया जाना चाहिए था। अब राज्य शासन को जो लाखों की राजस्व क्षति हुई हैं उसकी जवाबदारी किसकी हैं ?

कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के एक महीने बाद भी जांच व कार्यवाही का पता नहीं... लापरवाह, भ्रष्ट और बेलगाम हुए जिम्मेदार अधिकारी

इस सड़क निर्माण भ्रष्टाचार की शिकायत अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी द्वारा कलेक्टर जनदर्शन दिनांक 02/07/2024 को किया गया था, जनदर्शन में शिकायत होने के बाद दिनांक 10/07/2024 को कलेक्टर कार्यालय से इस डीएमएफमद से निर्मित सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में जांच करने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली को निर्देशित किया गया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कालोनी में डीएमएफ मद से ग्राम पंचायत करही द्वारा 14.98 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह सड़क निर्माण करीब 6-7 महिने पूर्व ही कराया गया है, परन्तु वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उक्त सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत करही द्वारा क्या मुंगेली नगर पालिका से सहमति या अनापत्ति प्रगाण पत्र लिया गया? और क्या ग्राम पंचायत करही को नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण का अधिकार है ?

उक्त शिकायत पर नियमानुसार जांच करते हुए, अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजने कहा गया।

कलेक्टर कार्यालय से कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली को जांच हेतु भेजे गए पत्र के करीब 25 दिनों बाद भी कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले जांच का अतापता नहीं हैं, क्योंकि आवेदक व शिकायतकर्ता को कोई सूचना जांच अधिकारी या विभाग की ओर से आज दिनांक तक नहीं दी गई हैं ऐसे में सवाल यह उठता हैं कि मामले को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा ? क्योंकि भ्रष्टाचारके इस मामले में कई अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं।

उपयोगिता (पूर्णता) प्रमाण पत्र में तीन और गुणवत्ता प्रमाण पत्र में दो अधिकारियों के हस्ताक्षर...

नगर पालिका के अवैध कालोनी में डीएमएफमद से निर्मित सड़क के भुगतान की राशि, लागत 14 लाख 55 हजार 5 सौ अट्ठारह रुपये बताया गया हैं और इसकी तकनीकी स्वीकृति 26/07/2023 को दी गई। गुणवत्ता प्रमाण पत्र में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग मुंगेली और उप अभियंता जनपद पंचायत मुंगेली के हस्ताक्षर हैं। वहीं उपयोगिता (पूर्णता) प्रमाण पत्र में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग मुंगेली और उप अभियंता जनपद पंचायत मुंगेली के हस्ताक्षर हैं। अब सवाल यह उठता हैं कि इतने बड़े-बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस सड़क की गुणवत्ता क्यों नहीं दिखी ? क्या इनके भी हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं ?

सूचना पटल भी नियम विरुद्ध... छिपाई जानकारी...

मुंगेली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 22/08/2023 को जारी कार्य आदेश में कार्य का नाम सीमेंट कांक्रीटीकरण सड़क निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग डायग्नोसिस सेंटर से आत्मा सिंह के घर तक की ओर, पंचायत का नाम करही, स्वीकृत वर्ष 2023-24, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक 1233/26.0./2024 तथा राशि 14.98 लाख उल्लेख हैं इस कार्य आदेश की कंडिका 11 में स्पष्ट लिखा हैं कि कार्य स्थल पर सूचना पटल तैयार कर सूचना पटल लगाया जावें, जिसमें कार्य से संबंधित सम्पूर्ण विवरण जिसमें योजना का नाम, कार्य का नाम, स्वीकृत वर्ष प्रशासकीय स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ होने का दिनांक, कार्य पूर्ण होने का दिनांक, कार्य की मूल्यांकित राशि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिला खनिज संस्थान न्यास मद का उल्लेख सहित कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य स्थल पर लगाया जावे। इसके बाद भी सूचना पटल में पूर्ण जानकारी नहीं लिखी गई, बल्कि जानकारी छिपाई गई, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों ने भी कुछ नहीं किया, इसके पीछे अधिकारियों की क्या मंशा होगी समझा जा सकता हैं।

कलेक्टर जनदर्शन में हुई थी शिकायत...

सड़क निर्माण भ्रष्टाचार की शिकायत अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में दिनांक 02/07/2024 को की गई शिकायत में बताया गया कि अभी हाल ही में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कालोनी में डीएमएफ मद से ग्राम पंचायत करही द्वारा 14.98 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य कराया गया हैं। जानकारी के मुताबिक यह सड़क निर्माण करीब 6-7 माह पूर्व ही कराया गया हैं, परंतु वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका हैं, गिट्टियां निकलकर बिखरी हुई है. जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिससे धूल भी बहुत ज्यादा होती हैं। सड़क निर्माण होते ही यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र को अवैध कालोनी मानते हुये कोई सडक नाली नहीं बनाया गया तो फिर ग्राम पंचायत करही किसके आदेश, किस नियम अधिनियम या आधार के तहत नगर पालिका क्षेत्र के अवैध कालोनी में सड़क निर्माण करायेगी। जबकि पूर्व में जिला प्रशासन को अवैध कालोनी में सड़क नाली संबंधी निर्माण कार्य न करने लिखित में भी दिया जा चुका है. क्योंकि सड़क, नाली, बिजली सहित कई मूलभूत सुविधा कालोनाईजर को नियमानुसार देना चाहिये। नगर पालिका के अवैध प्लाटिंग व अवैध कालोनी में ग्राम पंचायत करही द्वारा डीएमएफ मद से जो सड़क बनाया गया है उसमें भ्रष्टचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हैं। इससे राज्य शासन को भी भारी आर्थिक क्षति हुई हैं, इस सड़क निर्माण कार्य का जो बोर्ड लगाया गया है वह मुख्य द्वार पर न लगा अंतिम छोर में लगाया गया है ताकि किसी की नजर न पड़े और इस बोर्ड पट्टिका में कार्य प्रारंभ व समयसीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो अपने आप में संदेहास्पद हैं। साथ ही इस सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत करही द्वारा क्या मुंगेली नगर पालिका से सहमति या अनापत्ति प्रमाण लिया जाना चाहिए था या नहीं ? और क्या ग्राम पंचायत करही को नगर पालिका क्षेत्र के अवैध कालोनी में सड़क निर्माण का अधिकार हैं ? यह सब जांच का विषय हैं। मामले में दोषियों पर वैधानिक व कड़ी कार्यवाही की मांग की गई हैं।

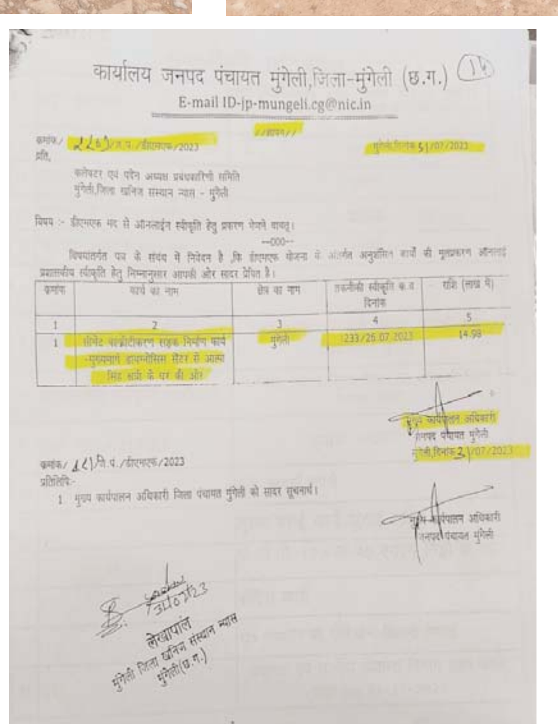

कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
E-mail ID-jp-mungeli.cg@nic.in

लेखापाल
मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास
मुंगेली (छ.ग.)

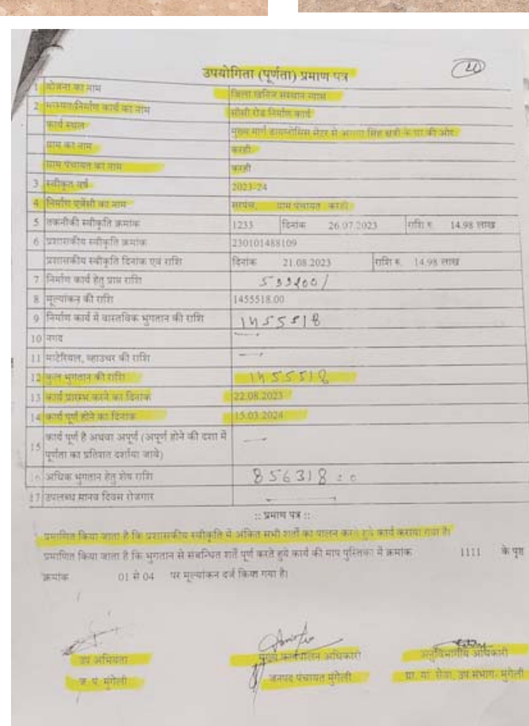

उपयोगिता (पूर्णता) प्रमाण पत्र

:: प्रमाण पत्र ::
प्रमाणित किया जाता है कि प्रशासकीय स्वीकृति में अंकित सभी शर्तों का पालन करते हुये कार्य कराया गया है।
प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान से संबन्धित शर्तें पूर्ण करते हुये कार्य की माप पुस्तिका में क्रमांक 1111 के पृष्ठ क्रमांक 01 से 04 पर मूल्यांकन दर्ज किया गया है।

उप अभियंता
ज.प. मुंगेली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मुंगेली

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रा. या. सेवा, उप संभाग- मुंगेली

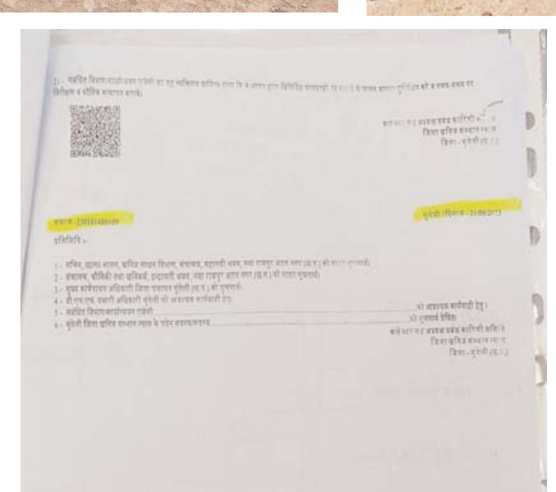

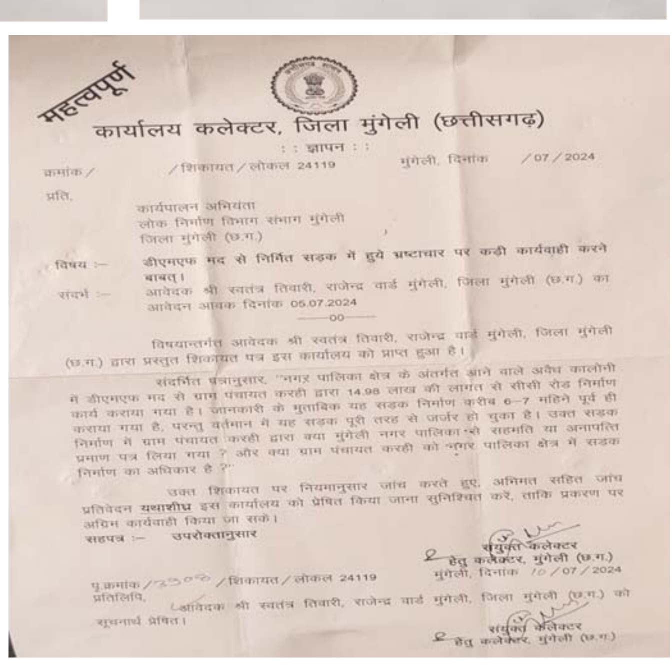

महत्त्वपूर्ण

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़)
:: ज्ञापन ::
क्रमांक / /शिकायत/लोकल 24119 मुंगेली, दिनांक /07/2024
प्रति,
कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग मुंगेली
जिला मुंगेली (छ.ग.)
विषय :- डीएमएफ मद से निर्मित सड़क में हुये भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाही करने बाबत्।
संदर्भ :- आवेदक श्री स्वतंत्र तिवारी, राजेन्द्र वार्ड मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) का आवेदन आवक दिनांक 05.07.2024
——00——
विषयान्तर्गत आवेदक श्री स्वतंत्र तिवारी, राजेन्द्र वार्ड मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
संदर्भित पत्रानुसार, "नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कालोनी में डीएमएफ मद से ग्राम पंचायत करही द्वारा 14.98 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह सड़क निर्माण करीब 6-7 महिने पूर्व ही कराया गया है, परन्तु वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उक्त सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत करही द्वारा क्या मुंगेली नगर पालिका से सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया ? और क्या ग्राम पंचायत करही को नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण का अधिकार है ?"
उक्त शिकायत पर नियमानुसार जांच करते हुए, अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।
सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
संयुक्त कलेक्टर
हेतु कलेक्टर, मुंगेली (छ.ग.)
पृ.क्रमांक/3505/शिकायत/लोकल 24119 मुंगेली, दिनांक 10/07/2024
प्रतिलिपि,
आवेदक श्री स्वतंत्र तिवारी, राजेन्द्र वार्ड मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
संयुक्त कलेक्टर
हेतु कलेक्टर, मुंगेली (छ.ग.)

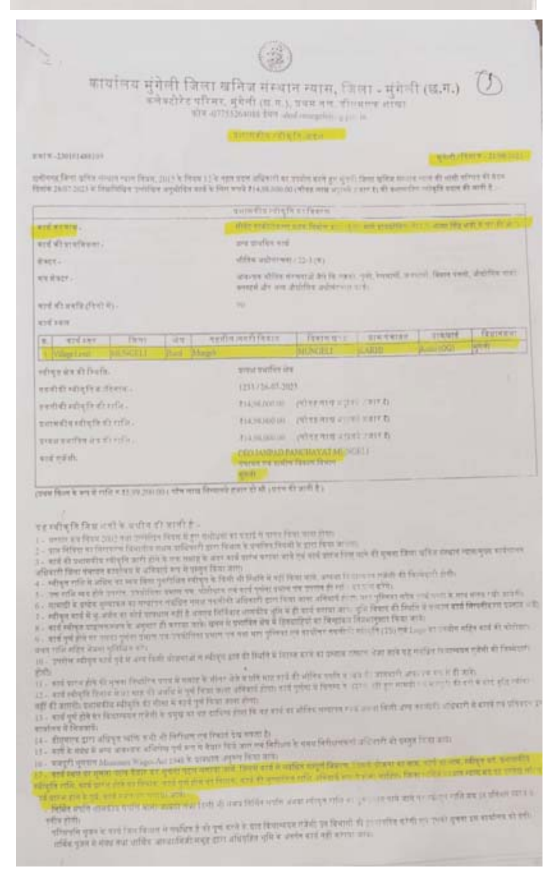

कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

इस प्रोजेक्ट में पहली बार साथ नजर आएंगे अर्जुन कपूर-खुशी कपूर

अर्जुन कपूर और खुशी कपूर ने इंस्टाग्राम पर दिलचस्प पोस्ट साझा किया और अपने इस क्रिप्टिक पोस्ट से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। दोनों ने इस पोस्ट के जरिए किसी नए प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया है। दोनों ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक लाइव आकर्षक साइनबोर्ड है, जिस पर लिखा है, मेरे खुशी अर्जुन आएंगे। इस पोस्ट को खास सिनेमाई अंदाज में डिजाइन किया गया है।

खुशी-अर्जुन दिखेंगे साथ

रहस्य और रोमांच से भरपूर इस वीडियो में दर्शकों को खास वाक्य के साथ उत्साहित किया गया। वीडियो में लिखा है कि पहले बार अर्जुन कपूर और खुशी कपूर साथ आ रहे हैं। इस वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में किसी प्रोजेक्ट के लिए डेब्यू करने वाले हैं और जल्द ही प्रशंसकों को भाई-बहन की यह जोड़ी किसी प्रोजेक्ट में साथ देखने को मिलेगी।

किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे साथ

हालांकि, इस प्रोजेक्ट का सटीक विवरण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो ने सफलतापूर्वक प्रत्याशा और उत्साह की भावना पैदा कर दी है। खुशी और अर्जुन कपूर पहली बार साथ काम कर रहे हैं, इसलिए प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह प्रतिभाशाली जोड़ी क्या लेकर आ रही है।

हिसाब के साथ डकैती की दुनिया रचने की तैयारी में विपुल अमृतलाल शाह

2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आंखें के लिए मशहूर विपुल अमृतलाल शाह अपनी नई फिल्म हिसाब के लिए तैयार हैं। इस आगामी डकैती वाली फिल्म ने इस बात की उम्मीद और बढ़ा दी है कि फिल्म निर्माता-निर्माता हीस्ट यूनिवर्स बनाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जिसमें रोमांचकारी बैंक डकैती और धमाकेदार एक्शन का एक नया दौर शामिल होगा। इंडस्ट्री के एक सूत्र के अनुसार, आंखें के बाद, विपुल अमृतलाल शाह ने एक और डकैती वाली फिल्म, हिसाब के साथ आने से पहले काफी समय तक इंतजार किया। हमने यह भी सुना है कि वह डकैती पर कुछ और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो इस फिल्म के बाद अगली फिल्म होगी। जब डकैती की बात आती है तो विपुल के पास बड़ी योजनाएँ हैं। जैसे-जैसे मनोरंजन उद्योग जासूसी थ्रिलर से लेकर पुलिस ड्रामा और कॉमेडी-हॉरर तक अपनी शैलियों के ब्रह्मांड का विस्तार कर रहा है, डकैती की शैली के भी इस दायरे में शामिल होने की उम्मीद है। इन सूत्रों ने खुलासा किया कि हिसाब के साथ, विपुल अमृतलाल शाह संभावित रूप से एक हीस्ट यूनिवर्स बना रहे हैं जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इस शैली के प्रशंसकों को लुभाना है। सूत्रों ने बताया कि 2002 में अपनी डकैती थ्रिलर आंखें की सफलता के बाद, उसी को फिर से बनाने के उद्देश्य से और साथ ही इस विरासत को जारी रखने की इच्छा के साथ, विपुल अमृतलाल शाह इस शैली को एक ब्रह्मांड के रूप में तलाशना चाहते हैं। फिल्म की बात करें तो इसमें मशहूर अभिनेता जयदीप अहलावत के साथ लोकप्रिय अभिनेत्री और विपुल की पत्नी शेफाली शाह भी होंगी।

सामंथा ने साझा किए 'सिटाडेल- हनी बनी' के अनुभव

वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु की सीरीज 'सिटाडेल- हनी बनी' की जब से घोषणा हुई है, प्रशंसक इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इसके टीजर ने उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। टीजर के साथ यह भी पता चला की सीरीज इस साल नवंबर में रिलीज होगी। अब सीरीज के प्रचार के दौरान साउथ अभिनेत्री सामंथा ने वरुण धवन के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया।

वरुण को सामंथा के काम ने किया प्रेरित

हाल ही में, सामंथा और वरुण की सीरीज का टीजर सामने आया। दोनों को जबरदस्त एक्शन भूमिकाओं में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज से जुड़ी तैयारियों पर बात करते हुए वरुण ने कहा कि उनकी तैयारी सामंथा की तुलना में आसान थी। अभिनेता ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह सार्वजनिक रूप से सबको पता है कि जब वह शो में आई थीं तो वह किससे जूझ रही थी। आप जानते हैं कि जब मैंने रिहर्सल करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इनके काम करने के तरीके को देखा तो उसने मुझे वास्तव में प्रेरित किया। वरुण के तारीफ करने के बाद सामंथा ने अपने सहयोग को साझेदारी बताया और कहा, यह एक साझेदारी थी, जैसे जब हम एक्शन करते थे, तो यह वास्तव में एक नृत्य की तरह लगता था। यह एक्शन रोमांटिक गीत की तरह लगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक तालमेल था। मेरे पास इतना तालमेल पहले कभी नहीं था क्योंकि राज और डीके राज और डीके हैं, उन्हें लंबे शॉट पसंद हैं, वे कट नहीं कहते। वरुण की प्रशंसा करते हुए, सामंथा ने कहा, जब से वह उठते हैं, उनके मन में केवल एक ही विचार होता है और वह यह कि मैं इस दृश्य को बेहतर कैसे करूं? वह हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह अपना काम बेहतर कैसे कर सकते हैं।'

सेट पर खुशनुमा रहते हैं वरुण

सामंथा ने कहा कि वरुण धवन उन सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं जिनसे वह कभी मिली हैं। उन्होंने उनके अद्भुत हास्य और सेट पर सभी को खुश रखने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी कोई बुरा दिन नहीं होता। उनके आस-पास हर कोई बहुत अच्छा है।'

बिग बॉस ओटीटी 3 विनर सना मकबूल ने कहा, मैंने अपना फोकस नहीं खोया

मैं बस ट्रॉफी जीतने आई हूं... ये वह डायलॉग है, जो बिग बॉस ओटीटी 3 में सबसे ज्यादा सुनाई दिया। कंटेस्टेंट सना मकबूल शो के पहले दिन से ही यह बोलती आई कि मुझे जीतना है और आखिरकार उन्होंने अपने इस जुनून को पूरा कर दिया और इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की। बिग बॉस ओटीटी 3 सना ने रैपर नैजी को हराकर जीता। विनर के तौर पर उन्हें 25 लाख रुपए मिले। जीतने के बाद, एक्ट्रेस ने शो में अपने सफर को लेकर बात की। उन्होंने कहा, पहले दिन से ही मैं बहुत क्लीयर और फोकस्ड थी कि मुझे ट्रॉफी जीतना है। लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने अपना फोकस नहीं खोया। मुझे लगता है कि अगर किसी चीज को लेकर आपके मन में जुनून हो, तो वह पूरी होकर रहती है। आखिरकार, मैं यहां हूं। लवकेश, विशाल और शिवानी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए सना ने कहा, मैं जल्दी रिश्ते नहीं बनाती। मेरा मानना है कि आप रियलिटी शो में दोस्त नहीं बनाते, लेकिन मैंने यहां दोस्त बनाए। लवकेश, विशाल और शिवानी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। सना ने अपने करियर की शुरुआत एक विज्ञापन से की थी, इसके लिए उन्हें 10 हजार रुपये मिले। इसके बाद वह 2009 में रियलिटी शो एमटीवी स्कूटी टीन डीवा में नजर आई। उन्होंने 2012 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और फेमिना मिस ब्यूटिफुल स्माइल का टाइटल जीता। वह म्यूजिकल सीरीज में भी दिखीं। साथ ही उन्होंने कई साउथ फिल्मों में भी काम किया। लेकिन लोकप्रियता उन्हें स्टार प्लस के सबसे चर्चित टीवी शो इस प्यार को क्या नाम दूं से मिली, जिसमें उन्होंने लावण्य का किरदार निभाया। उन्हें सोनी सब के आदत से मजबूर और कलर्स टीवी के विष में भी देखा गया था। वह खतरों के खिलाड़ी 11 में आईं और सेमीफाइनल तक पहुंची। इसके अलावा, उन्होंने कितनी मोहब्बत है 2 और अर्जुन में भी काम किया। अब वह बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर बनकर उभरी। शो जियो सिनेमा प्रीमियम पर स्ट्रीम हो रहा था।

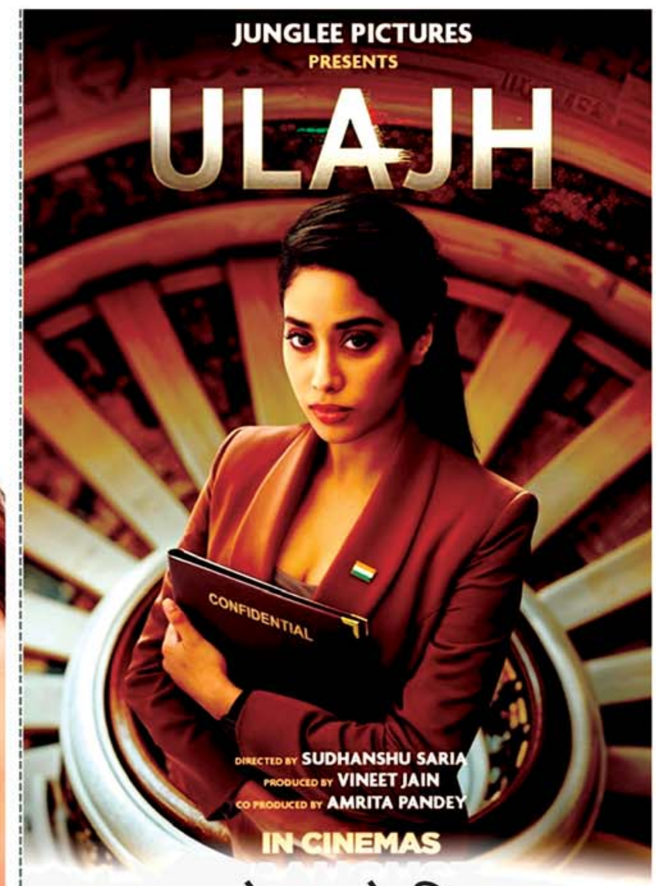

उलझ ने पहले दिन कमाए 1 करोड़, पिछले दो सालों में जाह्नवी की सबसे कमजोर फिल्म

उलझ ने पिछले दो सालों में जान्हवी कपूर अभिनीत किसी भी फिल्म के लिए सबसे कम ओपनिंग ली है। फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.10 करोड़ रुपये की कमाई की। व्यापक प्रचार के बावजूद, थ्रिलर अपने पहले दिन सिनेमाघरों में पर्याप्त दर्शकों को आकर्षित नहीं कर सकी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औरों में कहां दम था से टक्कर मिल रही थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 2 करोड़ रुपये की कमाई की थी। यह जान्हवी की मुख्य भूमिका वाली किसी फिल्म की लंबे समय में सबसे कम ओपनिंग थी। उनकी पिछली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही, जिसमें राजकुमार राव भी थे, ने इस साल की शुरुआत में मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद 6.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। उलझ एक जटिल शैली की फिल्म है और एडवांस बुकिंग से बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा। हालांकि, जिन दर्शकों ने इस फिल्म को देखा है वे इसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सुधांशु सरिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है और इसका असर निश्चित रूप से इसके वीकेंड कारोबार पर नजर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को इसके कारोबार में उछाल आएगा और उलझ पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ के आसपास कारोबार करने में सफल हो जाएगी।

उलझ को हॉलीवुड फिल्म डेडपूल और वूल्वरिन से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसे मार्वल के हार्ड कोर दर्शकों ने जबरदस्त सफलता दिलाने में मदद कर है। यह मार्वल की 34वीं फिल्म है और उम्मीद की जा रही है कि यह अपने दूसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी।

इसके अतिरिक्त उलझ को अमिताभ बच्चन की कल्कि 2898 एडी से भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। दर्शकों में अभी भी इस फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हुआ है, जो बॉक्स ऑफिस पर उलझ के कारोबार को प्रभावित कर रहा है।

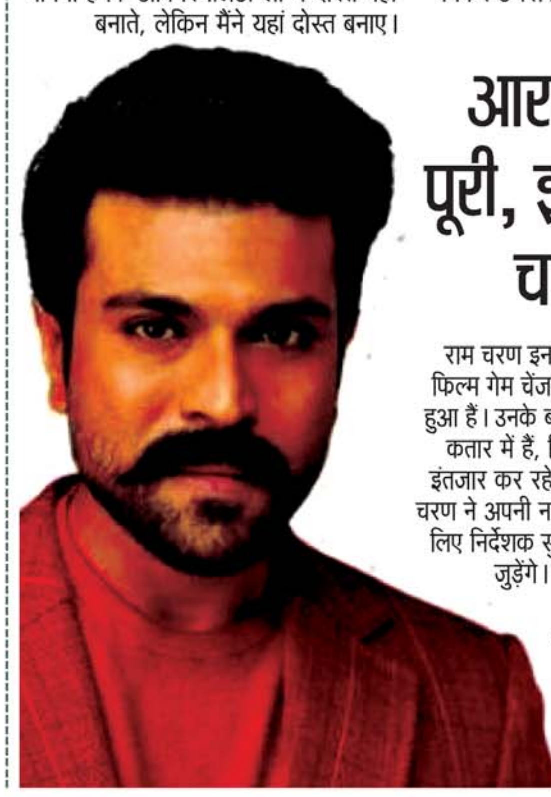

आरसी 17 की स्क्रिप्ट लगभग पूरी, इस दिन से शुरू होगी राम चरण की फिल्म की शूटिंग!

राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गेम चेंजर को लेकर चर्चा में बने हुआ हैं। उनके बाद अन्य कई फिल्में भी कतार में हैं, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में यह राम चरण ने अपनी नई फिल्म आरसी 17 के लिए निर्देशक सुकमार के साथ फिर से जुड़ेंगे। सुकुमार ने पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी की थी। वहीं अब इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर नई जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुकुमार के साथ राम चरण की फिल्म की शूटिंग अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी। सुकुमार-राम चरण की इस फिल्म को भी बड़े ही शानदार तरीके से लॉन्च किया गया था। वहीं अब इस फिल्म को लेकर ताजा जानकारी यह है कि इसकी स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा होने वाला है। वहीं बात करें राम चरण की आने वाली फिल्मों के बारे में तो गेम चेंजर के साथ अभिनेता के पास आरसी 16 भी है। कुछ दिन पहले अभिनेता ने अपनी नई फिल्म आरसी 16 के पूजा समारोह के बाद जान्हवी कपूर के साथ तस्वीरें साझा की थीं। इस फिल्म का निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए जान्हवी कपूर और राम चरण पहली बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

फिल्म में अलग अवतार में नजर आएंगे राम चरण

खबर है कि सुकुमार के लेखन विभाग में लेखकों की एक टीम शामिल हो गई है और उन्होंने राम चरण के लिए एक बेहतरीन भूमिका लिखी है। खबर यह भी है कि सुकुमार ने इस फिल्म में राम चरण के लिए एक क्रेजी लुक तैयार किया है। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। खबर यह भी है कि इस फिल्म को भी दो भागों में बनाया जाएगा, लेकिन निर्माताओं के मुताबिक यह सिर्फ एक भाग वाली फिल्म है।

स्टार पावर को लेकर बॉलीवुड पर भड़के अनुराग कश्यप, दक्षिण भारतीय फिल्मों को बताया बेहतर

निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में स्टार पावर पर जोर दिए जाने को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। अनुराग अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक प्रमुख कारण है कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्यप ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा कि बॉलीवुड अक्सर प्रामाणिक कहानी कहने की तुलना में स्टार पावर को प्राथमिकता देता है।

स्टार पावर को महत्व देता है बॉलीवुड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुराग कश्यप ने फहाद फाजिल अभिनीत फिल्म 'आवेशम' की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म के निर्माता महत्वपूर्ण भूमिकाओं में तीन प्रभावशाली लोगों को कास्ट करने में साहसी थे। उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड में, वह इन भूमिकाओं को बड़े सितारों से भर देते हैं, वास्तविक कहानी बताने के बजाय स्टार पावर पर ज्यादा जोर देते हैं।

इन फिल्मों की प्रशंसा की

अनुराग कश्यप ने कहा कि बॉलीवुड अक्सर दोहराए जाने वाले फार्मूलों पर काम करता है, लेकिन बॉक्स से बाहर निकलने पर असाधारण फिल्में बन सकती हैं। अनुराग ने पिछले साल आई फिल्म '12वीं फेल' और 'लापता लेडीज' की प्रशंसा करते हुए कहा कि मौलिकता ही उनकी सफलता की कुंजी है। उन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्म 'किल' की भी प्रशंसा की।

पहले भी कर चुके हैं आलोचना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुराने साक्षात्कार में फिल्म निर्माता-अभिनेता ने बॉलीवुड पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, 'बहुत सारा पैसा जो खर्च किया जाता है, वह फिल्म बनाने में नहीं जाता है। यह पैसे साज-सज्जा और दल-बल पर खर्च होता है।' उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि फिल्म निर्माण एक गंभीर उपक्रम है, जिसमें कड़ी मेहनत और रचनात्मकता शामिल है, न कि केवल एक आरामदेह गतिविधि। उन्होंने बताया था कि बजट का एक बड़ा हिस्सा उपकरणों और सहायक कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है।

जनसमस्या निवारण शिविर में मिले 87 आवेदन

फ्लड लाईट, पाथ-वे, मिनी गार्डन, जैसी मांगे आई शिविर में

प्रवेश गोयल/ सूरजपुर - नगरपालिका परिषद् सूरजपुर द्वारा 27 जुलाई से 10 अगस्त तक संचालित नगर सुराज अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन वार्ड क्र0-12, 13 एवं 14 में किया गया। जिसमें मांग एवं समस्या पर आधारित 87 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में नगरीय निकाय के संयुक्त संचालक वासुदेव चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष के.के अग्रवाल एवं सीएमओ मुक्ता सिंह चौहान ने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण की पहल की।

नगर के अग्रसेन वार्ड क्र0-12 मे आयोजित शिविर में 40 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें स्टेडियम ग्राउण्ड में फ्लड लाईट, पाथ-वे व शौचालय की मांग के साथ-साथ सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, मिनी गार्डन, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत समेत कई महत्वपूर्ण मांगो के आवेदन प्राप्त हुए। वार्ड क्र0-13 एवं 14 के लिए आयोजित संयुक्त शिविर मे कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मूलभूत सुविधाओं के विस्तार सड़क, बिजली, हैण्डपम्प, आंगनबाड़ी केन्द्र, सड़क व नाली की मरम्मत, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत समेत राशन कार्ड समेत अन्य आवेदन शामिल रहे।

संयुक्त संचालक एवं नपाध्यक्ष नें बांटे राशन कार्ड- शिविर निरीक्षण में पहुंचे संयुक्त संचालक वासुदेव चौहान एवं नपाध्यक्ष के.के अग्रवाल ने लोगों की समस्या सुनी और राशन कार्ड से वंचित तीन हित ग्राहियों का मौके पर ही राशन कार्ड बनवा कर वितरित किया।

पट्टा और मकान की मांगे भी आई शिविर में- जन समस्या निर्माण शिविर में लोगों ने अपने वार्ड विकास की दृष्टि से जहां एक ओर फ्लड लाइट, पाथ वे, लाइट, बिजली पोल, सड़क, नाली, हैंडपंप, मिनी पार्क जैसी मांगे रखी, वहीं दूसरी ओर वर्षों से काबिज भूमि का पट्टा और शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनाने की मांगे भी पहुंची।

इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवेश गोयल, पार्षद मंजू गोयल, पुष्पलता पवन साहू, एसडीओ. बसंत जायसवाल, राजेश राम, उपयंत्री अर्चना गुप्ता, प्रदीप एक्का राजस्व प्रभारी एमएल गहरवरिया, सीएस जायसवाल, उर्मिला सिंह, जितेन्द्र साहू, निरंजन राजवाड़े, संगीता सोनी, राजकुमार सोनी, गोपाल चक्रधारी, दिनेश साहू के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज सोनी, उषा पाण्डेय, जमीला बानो, रोशनी राज शर्मा समेत अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरमदेव में कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा

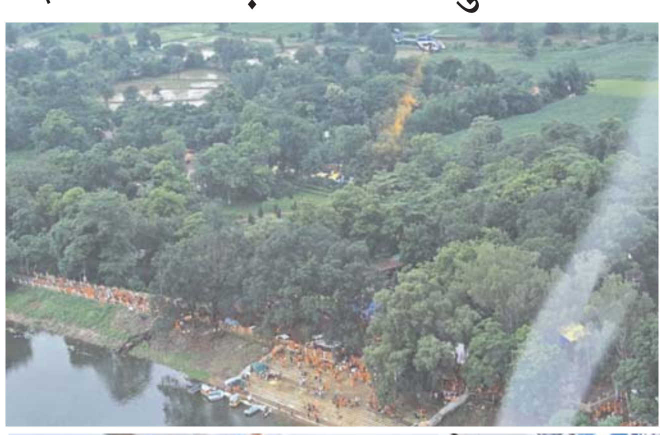

रायपुरः छत्तीसगढ़ में पहली बार कावड़ियों पर पुष्प वर्षा का अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जो उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सात्विक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के भोरमदेव में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सात्विक प्रयासों का फल- यह आयोजन श्री विजय शर्मा के निरंतर प्रयासों और श्रद्धालुओं के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता के कारण संभव हो पाया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, फ्रकभी सनातनियों पर लाठी बरसती थी, अब भोलेबाबा के भक्तों पर पुष्प बरस रहे हैं।फ्र इस कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को एक नई दिशा दी है।

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक क्षण- मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा का यह क्षण श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक रहा। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री स्वयं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया है। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को और भी सशक्त बनाने का कार्य हो रहा है।

सिमगा महाविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह संपन्न

चंद्रप्रकाश टोंडे : नई शिक्षा नीति के तहत हुए बदलाव, पाठ्य चयन और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में दी गई विस्तृत जानकारीफ्र.राजीव गाँधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा में सोमवार 05 अगस्त 2024 को दीक्षारंभ समारोह का आयोजन हुआ। नव प्रवेशी विद्यार्थियों को महाविद्यालय के वातावरण, विभागों, शैक्षणिक सुविधाओं और एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस जैसी सहगामी गतिविधियों से परिचित कराया गया।

समारोह में अतिथियों का स्वागत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मधुर गीत से हुआ। मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष भागवत सोनकर ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही विशिष्ठ अतिथिगणों में पार्षद श्रीमति स्वेता अभिजीत अवस्थी, कान्हा यदु, अब्दुल खान, चंद्रकुमार साहू पत्रकार चंद्रप्रकाश टोंडे ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य श्री बी एल बर्गह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य, मुख्य प्रावधान और नवीन अनुसंधान प्रणाली से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न कोर्सेज जैसे डीएससी, डीएसई, जीई, एईसी, वीएसी और एसईसी के बारे में जानकारी दी। बढ़ते क्रम में, जेनेरिक इलेक्टिव और वैल्यू एडिशन कोर्स समूहों की व्याख्या की। ताकि, विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार करियर विकल्प चुन सकें। हालिया बदलावों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, सतत आंतरिक मूल्यांकन और अंत सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। समारोह के अंत में, सहायक प्राध्यापक श्री आशीष यादव सहा. प्राध्यापक इतिहास और श्री विकास रात्रे सहा. प्राध्यापक वाणिज्य ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस सत्र में विद्यार्थियों को उनकी शंकाओं का समाधान मिला और वे महाविद्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं एवम सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में सु श्री अर्चना कुजूर सहा. प्राध्यापक वाणिज्य, सु श्री सुनीता साकेत सहा. प्राध्यापक वाणिज्य, श्री मति श्वेता एक्का सहा. प्राध्यापक रसायन शास्त्र, डॉ. मीना मेश्राम सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, डॉ संजोगीता तिवारी सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी, एवं निकटस्थ ग्रामीण अंचलों से आए विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स टीचर मीटिंग आज

कलेक्टर ने अभिभावकों को आमंत्रण पत्र जारी कर, मौजूद रहने की अपील

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 05 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 6 अगस्त को होने वाली संकुल स्तरीय पैरेंट्स टीचर मीटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। 198 संकुलों में यह बैठक एक साथ आयोजित की जा रही है। सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स टीचर मीटिंग पहली बार आयोजित की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में इसकी तैयारियों की विशेष समीक्षा की। उन्होंने इसके लिए अभिभावकों को अलग से आमंत्रण पत्र जारी कर बैठक में मौजूद रहने की अपील की है। कलेक्टर ने जारी आमंत्रण में कहा है कि नवनिहाल निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति और मध्यान्ह भोजन जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ लेते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों की शैक्षणिक प्रगति एवं भविष्य की संभावनाओं को तराशने में पालको का सहयोग अपेक्षित और अनिवार्य है। उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के प्रति सकारात्मक वातावरण और तनावमुक्त परीक्षा देने के लिए अभिभावकों से संवाद को जरूरी बताया है। गौरतलब है कि पैरेंट्स टीचर मीटिंग के सफल आयोजन के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें नियत तिथि और समय पर उपस्थित रह कर बैठक की सफलता में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सभी संकुलों में होगी।

पर्यटन का केंद्र खूंटाघाट डेम में तैरती हुई लाश, मछवारे ने देख पुलिस को दी सूचना

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- बिलासपुर में कर रहा था पीएससी का कोचिंग बेमेतरा का निवासी छात्र बिलासपुर से 3 दिनों से लापता था। डेम के सायकल स्टैंड में खड़ी थी स्कूटी, परिजन और पुलिस जुटी थी तलाश में प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा का रहने वाला भेक सिंह पिता गणेश सिंह बिलासपुर शहर के दयालबंद क्षेत्र में रहकर सीजी पीएससी की तैयारी कर रहा था छात्र की लाश आज सुबह 10 बजे के करीब खूंटाघाट डेम रतनपुर में मिली है, छात्र 3 दिनों से लापता था, मोबाईल स्विच ऑफ होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश में थे, वही परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से ही पुलिस भी छात्र की तलाश कर रही थी। इस दौरान सोमवार सुबह खूंटाघाट के मछवारो ने एक युवक की लाश डेम में तैरती हुई देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और लापता युवक के परिजनों को बुलवाया गया, जहाँ परिजनों ने मृतक की पहचान भेक सिंह पिता गणेश राम 26 वर्ष निवासी बेमेतरा के रूप में की वही पुलिस को युवक की स्कूटी भी खूंटाघाट के सायकल स्टैंड में 3 दिनों से लावारिस खड़ी होने की जानकारी मिली, जिसकी भी पहचान परिजनों ने कर ली है। मामले में पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी है, छात्र यहाँ किसके साथ पहुँचा था और उसके साथ क्या हुआ इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है।

एनटीपीसी लारा ने सहयोगी गांवों की महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया

रायगढ़। एनटीपीसी लारा ने 5 अगस्त को सहयोगी गांवों की महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए मशरूम की खेती और कृषि में उन्नत तकनीक के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एनटीपीसी लारा परियोजना के सात सहयोगी गांवों के स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की उपस्थिति में प्रेरणा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा शर्मा ने किया। संकाय सदस्य के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र, रायगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस राजपूत और डॉ. सीपीएस सोलंकी ने मशरूम की खेती और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग से लागत कम करने और लाभ को अधिकतम करने की तकनीक प्रस्तुत की।

सीएसआर-सीडी के तहत एनटीपीसी लारा ग्रामीण महिलाओं के कौशल उन्नयन के माध्यम से उन्हें सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है ताकि वे उस कौशल का उपयोग करके कमाई कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपने घर और पिछवाड़े में क्या बेहतरीन काम किया जा सकता है, इसका स्पष्ट प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र, रायगढ़ के वैज्ञानिकों ने किया। मानसून के दौरान धान की पराली का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम की खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। कम लागत और अपने खाली समय का सदुपयोग करके महिलाएं अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। साल भर अलग-अलग मौसम में अलग-अलग मशरूम की खेती की जा सकती है।

इस अवसर पर अरमुड़ा, देवलसुरा, महलोई, छपोरा, कांदागढ़ और बोड़ाझरिया गांव की 68 महिलाएं मौजूद थीं। साथ श्री जाकिर खान, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन, श्री राजेंद्र बहरा, उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) के साथ साथ नैगम सामाजिक दायित्व अनुभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सार-समाचार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा फ़्एक-पेड़ मॉ-के-नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत् किया गया वृक्षारोपण

कवर्धा। आज दिनांक 05/08/2024 माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के कवर्धा प्रवास के दौरान नया विश्राम गृह कवर्धा एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा प्रांगण में फ़्एक-पेड़ मॉ-के-नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत् 16 नग पौधा रोपण किया गया। हरीतिमा समूह कवर्धा द्वारा आयोजित उक्त पौधा रोपण कार्यक्रम में श्रीमती भावना बोहरा, विधायक पंडरिया, श्री अशोक साहू, पूर्व विधायक कवर्धा, श्री जन्मेजय महोबे, कलेक्टर कबीरधाम, श्री अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम, श्री संदीप अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम, श्री शशि कुमार, वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, हरितिमा के सदस्यगण, गणमान्य नागरिक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या मेंआमजन उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के मुख्य एवं प्रथम त्योहार हरेली में शासकीय प्राथमिक शाला-करनापाली में हुआ गेंड़ी दौड़ का आयोजन

जीत तिवारी/बसना। छत्तीसगढ़ की लोक पारंपरिक एवं प्रथम त्योहार हरेली पर्व का आयोजन बसना विकास खण्ड अंतर्गत संकुल केंद्र ढूटीकोना के शासकीय प्राथमिक शाला-करनापाली में दिनांक 05 अगस्त 2024 को बच्चों की प्रिय खेल गेंड़ी दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भैया बहनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और इसका खूब आनंद लिया। संस्था प्रमुख गिरधारी साहू ने बताया कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में छूपे प्रतिभा को निखरने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं शिक्षक वीरेंद्र कुमार कर ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ की धरा में ऐसे अनेक खेल है जिन्हें उभारने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में शामिल सरपंच खीरसागर पटेल शाला विकास समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल, कमल पटेल महेश पटेल हेमचरण सिदार स्वीपर कार्तिकमती नेताम,संजना नेताम ने भी इस कार्यक्रम का खूब आनंद लिया।

नये संभागायुक्त नीलम नामदेव एक्का ने कार्यभार ग्रहण किया

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 05 अगस्त 2024 को बिलासपुर के नये संभागायुक्त नीलम नामदेव एक्का ने आज कार्यभार ग्रहण किया। श्री एक्का वर्ष 2005 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। इसके पहले वे महानदी भवन मंत्रालय रायपुर में जन शिकायत निवारण, गृह एवं जेल विभाग के सचिव एवं संचालक विमानन के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत थे। कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर अवनीश शरण,नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने श्री एक्का का स्वागत किया। उन्होने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारी-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके काम-काज की जानकारी ली। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अर्चना मिश्रा एवं श्रीमती स्मृति तिवारी उपस्थित थीं। संभाग स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात कर स्वागत किया।

नवपदस्थ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने किया पदभार ग्रहण

जिला कार्यालय के विभिन्न विभागों एवं शाखाओं का किया अवलोकन, अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय समय पर आने के निर्देश

जीत तिवारी/महासमुंद। महासमुंद जिले के नए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज विधिवत पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि श्री विनय कुमार लंगेह वर्ष 2016 बैच के आई.ए.एस अधिकारी है। वे महासमुंद जिले के 23वें कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे कोरिया जिले में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही गरियाबंद जिले में जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात अधिकारियों से परिचय लेकर जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं और विभागों के कक्षों में पहुंचकर वहां का अवलोकन किया तथा वहां पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री लंगेह ने अवलोकन के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देवें। साथ ही रिकॉर्ड संधारण और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कार्यालय परिसर की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यों की जानकारी लेते हुए स्टाफ से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे आम लोगों से भी जानकारी लेते हुए समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री लंगेह ने जिला कार्यालय स्थित खाद्य विभाग, निर्वाचन शाखा, आबकारी, खनिज, कोषालय, भू-अभिलेख, एनआईसी, रिकार्ड रूम, हमर गोहार, चिप्स, राहत शाखा, अंत्यावसायी, लोक सेवा केन्द्र, स्थापना शाखा, आदिवासी विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री हरिशंकर पैकरा व श्री आशीष कर्मा, जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भूख जैसी समस्या का भी हल नहीं

रविशंकर

दुनियाभर के लिए भुखमरी आज एक वैश्विक समस्या बन गई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही विभर में भुखमरी का आंकड़ा भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

जबकि पृथ्वी पर हर एक इंसान का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में भुखमरी बढ़ती जा रही है।हकीकत ये है कि आधुनिक दुनिया में आज हर 11वां इंसान अभी भी खाली पेट सोने को मजबूर है। मतलब की दुनिया में 73.3 करोड़ लोग ऐसे हैं,जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। यदि 2019 की तुलना में देखें तो इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है।

अफ्रीका में हालात तो और भी कहीं ज्यादा खराब है, जहां हर पांचवां इंसान भुखमरी का सामना करने को मजबूर है। ये जानकारी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024' नामक ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से प्रकाशित की है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज दुनिया की एक तिहाई आबादी ऐसी है, जो पोषण युक्त आहार खरीदने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इनमें 86.4 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा

का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। वास्तविकता में देखें तो पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण का स्तर 2008-2009 के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि देखा जाए तो ये स्थिति तब है जब सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक किसी को खाली पेट न सोने देने की बात कही गई थी। मतलब की इन छह वर्षो में दुनिया को एक लंबा सफर तय करना है। रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर मौजूदा हालात इसी तरह से जारी रही, तो 2030 तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इनमें से आधे अफ्रीका में होंगे।

साफ है, दुनियाभर में तमाम प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बावजूद खाद्य असामनता और कुपोषण जैसे मुद्दे पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यूं तो इंसान पांच दशक पहले ही चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को चांद रोटी में नजर आता है। ताजा रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में भुखमरी की संख्या घटने की बजाए तेजी से बढ़ रही है। साफ है, भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी दुनिया को एक लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। ये कैसी विडंबना है एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझ कर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खानातक नसीब नहीं हो रहा है और वे भूख से जूझ और मर रहे है।

दुनिया भर में हर साल जितना भोजन तैयार होता है उसका लगभग एक-तिहाई बर्बाद हो जाता है। बर्बाद किया जाने वाला खाना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों के भोजन की ज़रूरत पूरी हो सकती है। गौर करने वाली बात ये है कि दुनिया में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही लोगों में खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, खाद्यान्न की क्षति और बर्बादी न केवल संसाधनों के कुप्रबंधन का मुद्दा है बल्कि ये बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान देती है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आठ प्रतिशत के लिए खाद्य अपशिष्ट भी जिम्मेदार होते हैं।

वर्तमान समय में हर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्पविकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए देशों की सरकारें प्रयास भी करती हैं तथा विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। यहां तक कि विकास दर के आंकड़े से ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे में जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए जो आपको ये बताए कि अभी तो देश 'भूख' जैसी 'समस्या को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े झूठे लगने लगते हैं। ये कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है।

संपादकीय

गरीबी मुक्त गांव बनाने की आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से गरीबी मुक्त गांव बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक के समापन अवसर पर शनिवार को कहा कि 2047 तक विकसित भारत, जो हर भारतवासी की महत्त्वाकांक्षा है, के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। यह दशक तकनीकी और भू-राजनीतिक बदलावों और अवसरों का है, जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित राष्ट्र के सफर में राज्यों की भागीदारी की बात कह रहे हैं, लेकिन बैठक में बिहार, केरल समेत 10 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में पहुंचीं जरूर लेकिन अपना भाषण बीच में ही रोक देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इतनी महत्त्वपूर्ण बैठक से दस से ज्यादा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का शामिल न होना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विकसित राष्ट्र की दिशा में अकेले-दुकेले की बढ़त से बात नहीं बनेगी। सभी की भागीदारी और सहयोग होना जरूरी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, गरीबी उन्मूलन और आबादी का प्रबंधन जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिनके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने तईं प्रयास करने होंगे। जरूरी बन पड़ी नीतियों को क्रियान्वयन करके देश के आर्थिक विकास की दिशा में अपना महती योगदान देना होगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह थी गरीबी-मुक्त गांव की दिशा में काम करने की। बेशक, इस दिशा में तैयारी करके बढ़ा जाए तो बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। माइक्रो लेवल का आर्थिक प्रबंधन कोई नहीं बात नहीं है। बहुत पहले गांधी जी ने गांव के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सक्रियता की बात कही थी। उन्हें लगता था, और जो भारत जैसे गांवों के देश में सही भी था, कि गांव के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देकर आमजन को सबल बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में इस आर्थिक सोच को बिसरा दिया गया।नतीजतन, गांव में रोजगार की स्थिति खासी चरमरा गई और बड़े पैमाने पर पलायन होने लगा। तमाम शहरों और बड़े नगरों की ओर हुए आबादी के पलायन से शहरों में नागरिक सुविधाओं के हालात बदतर हो गए। जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्यों में आरूढ़ सरकारें मिलकर गांवों को सबल बनाने की दिशा में अग्रसर हों जिससे आम जन के हालात बेहतर हो सकेंगे जो बड़ी सफलता होगी।

संसद में जाति पर जारी सियासी जंग के राजनीतिक मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडेय

वैदिक या सनातन सभ्यता-संस्कृति में जो 'जाति' कार्यकुशल जनसमूह की कार्यदक्षता की निशानी समझी जाती थी और राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई थी, वही जब लोकतांत्रिक या संवैधानिक सभ्यता-संस्कृति में व्यापक विवाद का वाहक बनकर दिन-प्रतिदिन अनुत्पादक प्रतीत होने लगे, तो देश व समाज के प्रबुद्ध लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए आज संसद में जाति के सवाल पर भाजपा नीत एनडीए और कांग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझने और आमलोगों को समझाने की जरूरत है।

पहला, चूंकि राजनीतिक दलों के लिए जाति अब सामाजिक ध्रुवीकरण का औजार और सियासी गोलबंदी का हथियार बन चुकी है, इसलिए उसे सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की जरूरत है, न कि नकारात्मक तरीके से। हां, अब जाति के परिप्रेक्ष्य में वह मुद्दा उठाने की जरूरत है, जिससे राजनीतिक दल और उसके 'चतुरसुजान' नेता अब तक बचते आए हैं। जैसे- साधुओं की जाति, वर्णसंकर लोगों की जाति और अंतरधार्मिक विवाह रचाने वाले लोगों और उनकी संततियों के धर्म का मुद्दा आदि सबसे अहम है। दूसरा, जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। क्योंकि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभाषों से भरे पड़े हैं। जिसकी वजह से उनमें स्पष्टता का अभाव तो है ही, लोकतंत्र की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी नदारत है। इस स्थिति के लिए हमारे राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस स्थिति को बदलने का साहस किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा, जिससे राष्ट्रीय हित और पेशेवर गुणवत्ता गहरे तक प्रभावित होती आई है जिससे वैश्विक मुकाबले में भारत पिछड़ता चला आया। तीसरा, जाति और धर्म के आधार पर बने कानूनों में व्याप्त विसंगतियों और इससे प्रभावित हो रहे सामान्य जनजीवन के खिलाफ स्वत: संज्ञान न लेकर न्यायविदों ने भी 'कालीदासी विद्वत्ता' का ही परिचय दिया है। जिस देश में वह लोकतांत्रिक न्याय दे रहे हैं, वहीं पर जब कानूनी व न्यायिक प्रावधान व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की पारस्परिक भावना को मुंह चिढ़ाने लगें, तो समझा जा सकता है कि मत समानता रहने के बावजूद पीड़ित व प्रभावित व्यक्ति कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। खास बात यह कि इस देश में जाति और जातीय आरक्षण की जो अवधारणा तय की गई है, सवर्ण-पिछड़ा-दलित-आदिवासी और उनकी गरीबी के अलावा अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के जो मानदंड तय किये गए हैं, वो तार्किक कम, प्रतिशोधी ज्यादा प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई इन्हें गलत ठहरा दे या उनमें संशोधन की बात करे। इससे तो यही लगता है कि संविधान निर्माताओं से लेकर संविधान के कथित संरक्षकों और संसद में पिछले लगभग 8 दशक से बैठ रहे अधिकांश माननीयों ने जनतांत्रिक कुएं में पड़ी भांग पी ली है, जिन्हें तर्क और तथ्य से कोई वास्ता नहीं, बस पददलित जनमानस पर निरंतर बिहंसते जा रहे हैं!

चतुर्थ, कुछ यही हाल राष्ट्र में जनमत निर्धारण करने में अमूल्य सहयोग देने वाली समग्र मीडिया इकाइयों और उसके अदूरदर्शी सम्पादकों का भी है, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की बजाय पक्षधरता भरी रिपोर्टिंग की और नीर-क्षीर विवेक वाक विद्या को

सियासतदानों के मन के मुताबिक जैसे तैसे परिभाषित किया। इससे जहां जनता गफ्लत में रही, वहीं संवैधानिक सिपहसालार मजे में! परन्तु कोढ़ में खाज यह कि जाति/सम्प्रदाय जैसे जनहित के मुद्दे जहां के तहां मील के पत्थर की तरह यथावत बने रहे। इसलिए हमारे राजनेता अपने मन के मुताबिक इनकी तरह तरह की व्याख्या करने में सफ्ल हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रहित प्रभावित होता है।

पांचवां, फ्लिवक्त भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो कुछ भी कहा, वह यदि सही नहीं है तो ज्यादा गलत भी नहीं है! लिहाजा, इस मुद्दे पर आधुनिक सोच विकसित करनी चाहिए। साथ ही कतिपय संवैधानिक/कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिए, ताकि कभी भारतीय समाज को माला की तरह जोड़ने वाली जाति प्रथा आरक्षण उत्प्रेरित सामाजिक टूट की वजह न बन जाये। जैसा कि महसूस किया जा रहा है इसलिए आरक्षण के आधार को जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार का किया जाना चाहिए, इसे रोटेशनल बनाकर सबको लाभान्वित किया जाना चाहिए, जो न्यायिक तर्क/वितर्क के मद्देनजर आसान नहीं लगता है।

छठा, उल्लेखनीय कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, जिन्हें अपनी जाति के बारे में भी नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। यह बात एक हद तक सही भी प्रतीत हो रही है! इसलिए ऐसे लोगों की जाति व धर्म के लिए भारत में स्पष्ट कानूनी प्रावधान तय किए जाने की जरूरत है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा हो। क्योंकि वैदिक जाति या धर्म की अवधारणा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसकी उपेक्षा संवैधानिक भारत में होना आम बात बन चुकी है।

सातवां, राहुल गांधी पर सदन में हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने इसके पहले ये भी कहा था कि असत्य के पैर नहीं होते हैं, जिसके चलते ये कांग्रेस के कंधे पर सवारी करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर सवारी करता है, वैसे ही राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। तभी तो अनुराग ठाकुर की इन टिप्पणियों पर सदन में हंगामा बढ़ गया। इसलिए सीधा सवाल है कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद सदन में जो जमकर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, वह कितना जायज है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है। यदि जनप्रतिनिधिगण हंगामा करने के बजाय तत्सम्बन्धी कानून बनाने की मांग करें तो ऐसे विरोधाभासों को टाला जा सकता है।

आठवां, संयुक्त विपक्ष हंगामा करने के बजाय उन लोगों की एक अलग जातीय कोटि व धार्मिक कोटि बनाने की मांग करे, जिनके माता-पिता भिन्न-भिन्न जातियों या सम्प्रदायों से है, क्योंकि उनकी संतान वर्णसंकर हुई। चूंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए यहां पिता की जाति या धर्म को स्वीकार करने की परम्परा प्रचलित है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इससे सम्बन्धित जाति/धर्म का मूलगुण दूषित/भ्रमित होता है। इसी तरह से साधुओं की भी एक अलग जाति बनाने की जरूरत है।

नौवां, आप मानें या न मानें, किंतु वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों के लिए ही वर्णसंकरता की परिकल्पना मौजूद है, जिसकी चतुराई और उसके संभावित दुष्परिणामों के बारे में वैदिक साहित्य द्वारा पहले ही आगाह किया जा चुका है। हालांकि, तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी लोगों के पास स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन का अभाव होने के चलते न तो वर्णसंकर लोगों की अलग जाति तय हुई और न ही अंतरधार्मिक शादी-विवाह करने वालों के लिए अलग धर्म तय किया गया। जबकि भारतीय समाज में इन्हें कहीं दोगलवा तो कहीं दुगामिया कहे जाने की परंपरा प्रचलित है, जिसे अबतक कानूनी वर्गीकरण हासिल नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि इस बहस के बाद इनका भी कानूनी वर्गीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को जातीय आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए या फ्रि किस कोटि से दिया जाए, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दसवां, सच तो यह है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जातीय जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर जो संग्राम मचा हुआ है, वह आगामी विधानसभा चुनावों व यूपी उपचुनाव के दृष्टिगत विपक्ष की एक सुनियोजित सियासी रणनीति है। इन सबके पीछे विपक्षियों की मौके पर चौका लगाने वाली रणनीति काम कर रही है, जिसके चलते 10 साल बाद ही सही पर वह संसद में मजबूत होकर लौटा है। तभी तो संयुक्त विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य 'वी वांट कास्ट सेंसस' के पोस्टर जब लहराने लगे, तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

ग्यारहवां, बीजेपी सांसद कांग्रेस पार्टी के सांसदों की हरकत की निंदा करते हुए अनुराग ठाकुर के बयान को सही बता रहे हैं। बीजेपी भी जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने भी राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आता कि वह बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं क्योंकि वह बात को कहीं और ले जाते हैं। वह कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अनुराग ठाकुर के बयान को उचित बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत की है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस दिन-रात जाति-जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ-पूछकर देश को बांटने की साजिश की है और जब सदन में जाति की बात हुई तो राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। ये देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वह सबसे जाति के बारे में पूछे और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकता। ये गंभीर मामला है। हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।

इसे भी पढ़ें: क्या बीजेपी के लिए लंबे समय तक चुनौती बनेगा राहुल और अखिलेश का गठबंधन?

बारहवां, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि जातीय राजनीति अब चुनाव मैदान होते हुए देश की संसद तक पहुंच चुकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की सफ्लता ने पूरे देश में ऐसी गोलबंदी को शह देने के रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए ऐसी बहस सीधे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आमने-सामने हो रही है। जिसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की, और फ्रि अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभालकर उसमें तड़का लगा दिया।

ऐसे में पुन: सवाल वही कि जो लोग जाति, जातीय आरक्षण और जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, उन्हें समाज के दो प्रमुख आरक्षण वंचित समूह संपन्न सवर्ण और मुसलमान के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनकी जातीय सोच कुंठित नहीं हो। इसके अलावा, जातीय आरक्षण को रोटेशनल बनाकर इसे एकल पदों पर भी लागू किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ही जाति या परिवार के लोगों की बहुतायत सिस्टम में न हो। जैसा कि अभी देखा-सुना जा रहा है। वहीं, जिस व्यक्ति को इसका एक बार लाभ मिल गया, उसे दूसरी बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

तेरहवां, ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि क्या भाजपा में इस मुद्दे पर होने वाले नफ्त-नुकसान के बारे में भी किसी ने सोचा है या फ्रि बीच बहस में कूद पड़े हैं? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर में हुई जातीय बहस का फायदा एनडीए को मिलेगा या इंडिया ब्लॉक को, या फ्रि दोनों को? क्योंकि जातीय सर्वे तो कतिपय राज्यों में पहले से भी होते आये हैं। हां, इनके आंकड़े भी जारी किये जायें, ऐसा कभी जरूरी नहीं लगा। इसलिए यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यह बात दीगर है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक मजबूत राजनीतिक आधार मिला, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी तेजस्वी यादव को साथ लेकर इस दिशा में एक निर्णायक पहल की। ततपश्चात बिहार में जातीय जनगणना कराई गई और विधानसभा में पेश किये जाने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन पहले पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर भी लगा दी।

नव तस्करी के खिलाफ लड़ाई

राजेश मणि

नव तस्करी के खिलाफ हमारी लड़ाई में, हमें लगातार नवाचार के माध्यम से जुड़ने और एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के हमारे उपयोग का अनुकूलन भी शामिल है। तस्कर दूसरों का शोषण करने के लिए इंटरनेट की लगातार बदलती प्रकृति का लाभ उठाते हैं; यह जरूरी है कि हम भी इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएं। डिजिटल तकनीक ने हमें तस्करी को रोकने, पीड़ितों की रक्षा करने, बुरे लोगों पर मुकदमा चलाने और इस अपराध से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने के नए तरीके दिए हैं। डिजिटल तकनीक और मानव तस्करी के बीच एक तरह का संबंध तब हो सकता है जब तस्कर पीड़ितों का शोषण करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान दिया गया क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के चरम पर अपनी दैनिक गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया। कई देशों की रिपोटरे ने ऑनलाइन वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन तस्करी में भारी वृद्धि को प्रदर्शित किया, जिसमें बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण, और बाल यौन शोषण सामग्री की मांग और वितरण शामिल है। तस्करों ने पीड़ितों को तैयार करने, धोखा देने, नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके व्यक्तियों का शोषण करने की योजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इनमें से कुछ योजनाएं लोगों को सैकड़ों मील दूर, सीमाओं के पार भी लुभाती हैं, जबकि अन्य के लिए उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। मानव तस्करी के पीड़ितों और बचे लोगों ने तेजी से साझा किया है कि वे पहली बार अपने तस्करों से ऑनलाइन जुड़े थे, जबकि तस्कर डिजिटल तकनीकों के अपने उपयोग को परिष्कृत और उन्नत करना जारी रखते हैं, सरकारों और अन्य तस्करी विरोधी हितधारकों को मानव तस्करी से निपटने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तस्कर संभावित पीड़ितों की पहचान और उन्हें तैयार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यूएनओडीसी के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तस्करों को सक्रिय रूप से और गुमनाम रूप से एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति की खोज करने में मदद करते हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील हैं (शिकार प्रक्रिया), या ऑनलाइन पोस्ट करके और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करके संभावित पीड़ितों को निष्क्रिय रूप से आकर्षित करते हैं (मछली पकड़ने की प्रक्रिया)। अपराधी संभावित पीड़ितों के साथ बातचीत करते समय नकली खातों और प्रोफाइल के माध्यम से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन, वेबसाइट, डेटिंग ऐप और गेमिंग प्लेटफॉर्म-या ऐसे उपकरणों की धोखाधड़ी या भ्रामक नकल-का उपयोग कर सकते हैं।

एक बार जब संभावित पीड़ितों की पहचान हो जाती है और संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से संचार शिक्षा, रोजगार, आवास या रोमांटिक संबंधों के झूठे वादों के साथ व्यक्तियों को धोखा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, केवल उन्हें श्रम और यौन तस्करी की स्थितियों में लुभाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक तस्कर एक ऑनलाइन व्यावसायिक वेबसाइट बना सकता है, जिस पर वे अक्सर पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए यथार्थवादी तस्वीरें शामिल करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अवसर प्रामाणिक है और उनके करियर को आगे बढ़ाने या उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इंटरनेट शोषणकारी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है, जिसमें सेक्सटॉर्शन के माध्यम से भी शामिल है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) सेक्सटॉर्शन को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित करता है जो तब होता है जब अपराधी पीड़ित द्वारा यौन प्रकृति की तस्वीरें, यौन एहसान या पैसे न दिए जाने पर निजी और संवेदनशील सामग्री वितरित करने की धमकी देता है। इसके अतिरिक्त, तस्कर जबरन अपराध को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जो एक तेजी से आम तंत्र है जिसमें तस्कर अपने पीड़ितों को ऑनलाइन घोटाले के संचालन से लेकर व्यावसायिक सेक्स तक के कामों में शामिल होने या उनका समर्थन करने के लिए मजबूर करते हैं। तस्कर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन नौकरी लिस्टिंग के माध्यम से पीड़ितों को भर्ती करते हैं, उन्हें परिसरों में बंद कर देते हैं और गंभीर नुकसान की धमकी देकर उन्हें ऑनलाइन आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। ऑनलाइन घोटाले के संचालन में अवैध ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजनाएं और रोमांस घोटाले शामिल हैं, जिनमें से सभी में तस्करी का शिकार व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है ताकि उन्हें महत्त्वपूर्ण रकम का धोखा दिया जा सके। संक्षेप में, तस्कर अपने तस्करी कायरे की पहुंच, पैमाने और गति को बढ़ाने के लिए इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। हालांकि तकनीकी विकास के साथ तरीके और साधन विकसित हो सकते हैं, लेकिन तस्करी के मूल में शोषण अभी भी जारी है, जो इस अपराध की जांच और उससे निपटने के लिए व्यापक और अभिनव दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हम सभी को विशेषकर बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है या मॉनिटिरंग करने की आवश्यकता है। तस्कर आए दिन अपने तरीके बदलते रहते हैं।

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक

आयुष्मान कार्ड निर्माण में लाएं प्रगति - कलेक्टर

ग्राम पंचायत कोसा में 6 अगस्त को होगा जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन, आवश्यक तैयारी करने के दिए निर्देश

''स्वास्थ जांजगीर-चांपा'' अभियान के तहत शतप्रतिशत सर्वे व सैम्पल जांच करने के दिये निर्देश

जांजगीर-चांपा/ कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परेड एवं रिहर्सल, आमंत्रण कार्ड, बैठक व्यवस्था, साज-सज्जा, बेरिकेटिंग, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरटीई के सभी नोडल अधिकारियों को ऐसे आरटीई के ड्रापआउट छात्र-छात्राएं का चिन्हांकन कर कारण की जानकारी लेने कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के पदों पर भर्ती की जानकारी लेते हुए शेष पदों पर समयसीमा में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विभागों से खाली पदों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसा में 6 अगस्त को आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर में सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित

अधिकारियों को जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार व सीएमओ को शिवरीनारायण में जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लगातार कार्य करते रहें और मितानिन भी लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को बीएमओ से समन्वय कर शेष लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रगति लाने के निदेश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों को शिविर में जाकर आयुष्मान कार्ड निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने पीएम किसान योजना में पात्रता की जांच कर अधिक से अधिक पंजीयन करने कहा। कलेक्टर श्री छिकारा ने कहा कि 27 अगस्त को बम्हनीडीह में आयोजित होने वाले दिव्यांगता जांच शिविर के लिए आवश्यक तैयारी करे। उन्होंने संबंधित अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र बनाने में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ''स्वस्थ जांजगीर चांपा'' अभियान के तहत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए शेष बचे सर्वे एवं सैम्पल जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में खाद-बीज के स्थिती की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मृतक व्यक्ति के वन अधिकार पत्र के नामांतरण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, समय सीमा के प्रकरण, कलेक्टर जनदर्शन और जनशिकायत, चौटबोट संवाद 24म7 के प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित विभागों को समय-सीमा कर अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्कृष्ट जांजगीर-चांपा अभियान, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, पीएम जन आरोग्य योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, अग्निवीर, पीएम विश्वकर्मा, महतारी वंदन योजना, केसीसी की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ श्रीमती प्रियंका पांडेय, सहायक कलेक्टर श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री एसपी वैद्य, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल कुमार रावटे सहित जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

घर के बाहर बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ : गांव में दहशत, पुलिस- वनकर्मियों ने शुरू की तलाशी

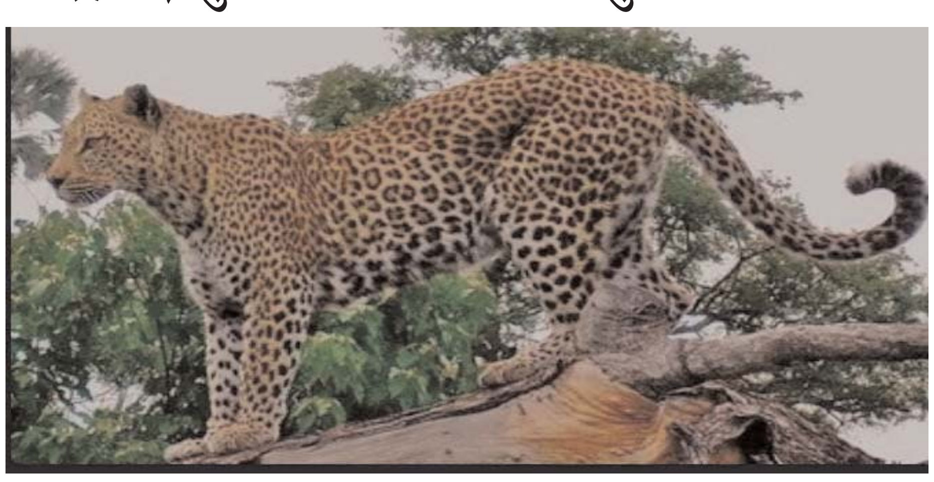

अशोक लुनावत /कांकेर/ छत्तीसगढ़ के धमतरी, सिहावा क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां 3 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और परिवार के लोग अंदर खाना खा रहे थे। जब पिता बाहर आए तो बच्चे को गायब पाया। बहुत खोज- बीन करने पर भी कोई पता नहीं चलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामला सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरमुड़ की है। यह इलाका धमतरी जिले में आता है। यहां कमार परिवार की बस्ती है, जो जंगल पहाड़ी बांध से लगा हुआ है। घटना रविवार शाम लगभग 7 बजे की है। पूरी बस्ती के लोग हरेली के त्योहार मना कर अपने अपने घर जा चुके थे। योगेश्वर मरकाम भी अपने परिवार संग घर के अंदर खाना खाने लग गए। इधर उनका बेटा तिरेश मरकाम खाना खाकर बाहर खेलने चल दिया। थोड़ी देर बाद जब योगेश्वर घर के बाहर निकला तो उसे तीरेश दिखाई नहीं दिया। सभी उसे ढूंढने में लग गए जब नहीं मिला तो पुलिस को खबर की गई।

लापता बच्चा - वन कर्मी और पुलिस मिलकर चला रहे तलाशी अभियान पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के पास जंगली जानवर के पैरों के निशान होना पाया गया। इससे किसी जंगली जानवर के उठा ले जाने की आशंका है। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई है। वन विभाग के कर्मचारी भी मौके का मुआयना करने पहुंचे। वनकर्मियों ने पाया कि शायद तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया है। वन विभाग और पुलिस की टीम खोज बीन में लगी हुई है। उधर परिवार का रो- रो कर बुरा हाल है। इस घटना से बस्ती वाले दहशत में हैं, यह सोचकर कि पता नहीं कौन सा नरभक्षी गांव में घूम रहा। है

श्रीरामलला दर्शन योजना : लॉटरी से 72 दर्शनार्थियों का चयन

अयोध्या धाम दर्शन के लिए 22 अगस्त को होगा दल रवाना

अशोक लुनावत/ कांकेर, श्रीरामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम की यात्रा के लिए दर्शनार्थियों के चयन हेतु आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में चयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में जिले के नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत लॉटरी के माध्यम से 72 दर्शनार्थियों का चयन किया गया। जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत तीसरे चरण की यात्रा के लिए आज लॉटरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से 54 दर्शनार्थियों का चयन किया गया, वहीं नगरीय क्षेत्र से 18 दर्शनार्थियों का चयन किया गया। उक्त चयनित दर्शनार्थियों को जिला मुख्यालय से 22 अगस्त को अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दर्शनार्थियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के साथ स्वास्थ्य विभाग को विकासखण्ड स्तर पर ही चयनित हितग्राहियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर समिति के सदस्य श्री बृजेश चौहान सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, हटाए गए समन्वयक विनोद गुप्ता

लखनपुर के गुमगरा संकुल का मामला, विरोध प्रदर्शन के बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारीयों ने कारवाई

भारत भास्कर ब्यूरो/ अम्बिकापुर -जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम गुमगरा कला संकुल केंद्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों में स्वीपर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों और सरपंचों के द्वारा सरगुजा कलेक्टर से पूर्व में शिकायत की गई थी। कटकोना माध्यमिक शाला में निरीक्षण करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राय से ग्रामीणों ने सुपर भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत की इसके खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राय की उपस्थिति में संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता द्वारा कांग्रेसियों सरपंचो और ग्रामीण को जांच करने की धमकी दिया गया। किसी ग्रामीण के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। सरपंचों कांग्रेसियों और ग्रामीणों को धमकाने के बाद आक्रोशित सरपंच और ग्रामीणों ने पुन: सरगुजा कलेक्टर को आवेदन दिया था। आवेदन में उल्लेखनीय है की तीन दिवस के भीतर तीन संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता के खिलाफकार्रवाई नहीं होने की स्थिति में गंगारा कला संकुल केंद्र के स्कूलों में सरपंचों और ब्राह्मणों के द्वारा ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 5 अगस्त सोमवार को पांच गांव के सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल बंद करने पहुंचे थे सूचना उपरांत लखनपुर तहसीलदार थाना प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी सहायक खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। और समझाइए देने लगे जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिंह के द्वारा संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता को पद से हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया तथा प्रशासनिक टीम ने संकुल सम्मेलन विनोद गुप्ता के खिलाफजांच कर

कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए विरोध प्रदर्शन समाप्त कराया गया।धर्मेन्द्र कुमार झरिया पूर्व जनपद सदस्य, नंदलाल सिंह सरपंच परसोडी कला ,लोकनाथ उर्रे सरपंच गुमगरा कला, विजय सिंह सरपंच गुमगराखुर्द, सुखसाय पोर्ते सरपंच कोरजा, सुमित राम सरपंच प्रतिनिधि कटकोना, गोवर्धन उपसरपंच, अवधेश राजवाड़े उप सरपंच बगदर्री, रमेश साहू, काशिम सिंह, हलेश्वर राजवाड़े, करीमन राजवाड़े, सुनील मरकाम आदि पाचो पंचायत के बहुत सारे ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जारी आदेश को लेकर के लोगों में संशय- वर्तमान में संकुल समन्वयक को उनके संकुल समन्वयक के पद से हटाए जाने के आदेश जारी जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के द्वारा कर उन्हें मूल पद शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कटकोना पदस्थ किया वही इस आदेश को देखते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कटकोना से भी शिक्षक पद पर हटाए जाने हेतु निवेदन किया गया था लेकिन वर्तमान में आधा अधूरा कार्यवाही करके लोगों को संशय में डाल दिए हैं।वही आगे प्रदर्शन कारियो के द्वारा कहा गया कि यदि उक्त शिक्षक को जल्द शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक पद से हटकर अन्यंत्र नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में भी बड़ी हड़ताल की जाएगी जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन का रहेगा, ।

जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा- वही संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आशोक सिन्हा के द्वारा बताया गया कि उन्हें अब संकुल समन्वयक के पद से हटाकर मूल पद शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कटकोना में शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।गुमगराकला के संकुल समन्वयक पद से हटाए जाने के पश्चात स्वत ही गुमगरा खुर्द का अतिरिक्त प्रभार समाप्त हो गया है।

तहसीलदार अंकिता पटेल- इस संबंध में लखनपुर तहसीलदार अंकिता पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गुमगरा कला संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता के द्वारा सरपंचों और ग्रामीणों से बदतमीजी अभद्र व्यवहार किया था। सरपंचों और ग्रामीणों की बात सुनी गई। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संकुल समन्वयक को पद से हटा दिया गया है। 6 अगस्त को होने वाले मेघा पालक बैठक के संबंध में भी सरपंचों और ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई।

खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राय- खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राय ने बताया कि 26 जुलाई को उनके समक्ष संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता द्वारा सरपंचों और ग्रामीणों को सरपंचों औरग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार कर धमकी दिया गया था। इसके बाद जांच प्रतिवेदन बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर संकुल समन्वय को पद से हटा दिया गया है।

सार-समाचार

कार में बैठकर ऑन लाईन सट्टा का संचानल,एक गिरफ्तार

दुर्ग। जिले की भिलाई भट्टी पुलिस ने कार में बैठकर ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 2 नग मोबाईल, 05 नग एटीएम कार्ड, 05 नग सीम कार्ड, नगदी रकम 1043 रूपये, एक स्वीफ्ट डिजायर कार बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए ऑनलाईन महादेव सट्टा गैंमिग अपराधों पर अंकुष लगाने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा ऑनलाईन सट्टा कारोबारियों पर प्रभावी करने हेतु निर्देश दिये गये है। जिसके परिपालन में थाना भिलाई भट्टी के द्वारा एक संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही हेतु लगाया गया था टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में सूचना संकलन किया जा रहा था तथा संदेहियो पर सतत निगाह रखी जा रही थी इसी दौरान दिनांक 4 अगस्त को सूत्रो से पता चला कि हर्ष कुमार निवासी खुर्सीपार नाम का व्यक्ति स्वीफ्ट डिजायर कार में विवेकानंद गार्डन सेक्टर 01 भिलाई के पार्किंग में कार को खड़ी करके कार के अंदर बैठकर ऑनलाईन गैमिंग सट्टा का कारोबार मोबाईल फोन के माध्यम से कर रहा है। सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर विवेकानंद गार्डन के पास स्वीफ्ट डिजायर कार क्रंमाक सीजी 07 सीएम 6044 के अंदर बैठे हुये व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ किया। प्रारंभिक पूछताछ पर हर्ष पुलिस को गुमराह करता रहा किन्तु कड़ाई से तथ्यात्मक पूछताछ करने उसने ऑनलाईन गैंमिग सट्टा रेड्डी अन्ना 128 नंबर पैनल के माध्यम से सट्टा खिलाने की बात स्वीकार की। जिसके बाद उसके मोबाईल का निरीक्षण करने पर उसमें उक्त ऑनलाईन गैमिंग सट्टा के 6,37,330 रूपये पैसो के लेनदेन के संबध में हिसाब किताब व व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद मिला। आरोपी के द्वारा ऑनलाईन गैंमिग सट्टा के कारोबार में उपयोग किया जा रहा 02 नग मोबाईल फोन, 05 नग विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड, 05 नग सीम कार्ड, नगदी रकम 1043 रूपये को व घटना में प्रयुक्त कार स्वीफ्ट डिजायर क्रंमाक सीजी 07 सीएम 6044 जुमला किमती 8,73,000 रूपये को आरोपी के कब्जे से मौके पर कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना भिलाई भट्टी में धारा 7,8 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

सट्टा संचालित करते दो गिरफ्तार

दुर्ग। जिले की पुरानी भिलाई पुलिस ने सट्टा पट्टी लिखते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से सट्टा पट्टी तथा 54930 रूपये नगदी रकम जब्त किया है। मामले में आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्यवाही की गइे है। मिली जानकारी के अनुसार थाना पुरानी भिलाई क्षेत्रांतर्गत 3 अगस्त को थाने की टीम भिलाई 03 क्षेत्र में टाउन भ्रमण पर रवाना हुई थी। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि पानी टंकी के पास दादर रोड चरोदा में दो व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख कर हार जीत का दांव लगा रहे है। जिसपर मौके पर पहुंचकर टीम ने रेड कार्यवाही करते हुए मौके पर दो व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते हुए पाया और उन्हें मौके पर पकड़ा गया । पुछताछ में आरोपियों ने अपना नाम प्रफुल्ल प्रधान उर्फ जापानी निवासी चरोदा तथा विनोद सिंह निवासी चरोदा बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से पृथक-पृथक प्रफुल्ल प्रधान उर्फ जापानी निवासी चरोदा के कब्जे से 06 नग सट्टा पट्टी, नीले स्याही का डाट पेन एवं नगदी रकम 52600रूपये एवं विनोद सिंह निवासी चरोदा के कब्जे से 02 नग सट्टा पट्टी, एक नीले स्याही का डाट पेन, नगदी रकम 2330 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्यवाही की गइे है।

निवेशकों के लिए सावधानी

मुंबई : एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि श्री जेम लाल देवांगन (पैन: (त्तष्टक्क1320छ), हमारे पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर में से एक के अधिकृत व्यक्ति, नीचे उल्लिखित पते के माध्यम से काम करते हुए, शेयर बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न प्रदान कर रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडिंग सदस्य के खिलाफअनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है।

पता- बीएल.नंबर 27, प्लॉट नंबर 22, दूसरी मंजिल व्हाइट हाउस, नेहरू नगर, पूर्वी भिलाई, दुर्ग-490020, छत्तीसगढ़।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक /सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न देने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी योजना/उत्पाद को सब्सक्राइब न करें क्योंकि ऐसा करना कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और उसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker लिंक के तहत अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/ढूंढें की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से/को पैसे प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए क्लाइंट बैंक खातों के रूप में नामित नामित बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए गए हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति/संस्था के साथ लेन-देन करते समय विवरण की जांच करें।

स्कूटर सहित 50 लाख का सोना चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग के सुपेला थानाक्षेत्र में एक सराफा कारोबारी की गाड़ी से करीब 50 लाख का सोना चोरी हो गया। कारोबारी ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई दी और पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला 25 जुलाई का है। वैशाली नगर निवासी सागर हिम्मत जरे ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह दुर्ग स्थित जेबीआर रिफाइनरी में सोना गलाने का काम करता है और घटना वाले दिन वह रात 9 बजे सोना लेकर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में अंसारी बिरयानी दुकान के सामने अपनी स्कूटर खड़ा किया और खाना खाने के लिए अंदर चला गया। जब वह वहां से खाना खाकर निकला तो देखा कि उसका स्कूटर चोरी हो गया है और उसकी स्कूटर की डिग्गी में 50 लाख रुपये कीमत का करीब साढ़े सात सौ ग्राम सोना रखा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें देखा गया कि दो लोग रेनकोट पहन कर कारोबारी की स्कूटर ले जाते नजर आए। जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच करते हुए दोनों का पता लगाया। जिसमें दोनों की पहचान नरेश सोनी और आनंद सोनी के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पता लगाते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से चोरी हुई गाड़ी तथा सोना जब्त कर लिया है।

देश की 75 हजार ग्राम पंचायतों में हो रहा डिजिटल कामकाज

बड़े राज्यों से आगे छोटे सूबे

देश में ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रान्सफोर्मेशन करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसमें से देश में कुल 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ रेडी कैटेगरी में है। इनमें से देश में 75002 पंचायते हैं जो डिजिटल रूप से कामकाज कर रही हैं। जिसमें से गुजरात में 11465 पंचायते हैं जिनका कामकाज डिजिटल में शुरू हो चुका है।

मुंबई

देश में ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रान्सफोर्मेशन करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसमें से देश में कुल 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.18 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ रेडी कैटेगरी में है। इनमें से देश में 75002 पंचायते हैं जो डिजिटल रूप से कामकाज कर रही हैं। जिसमें से गुजरात में 11465 पंचायते हैं जिनका कामकाज डिजिटल में शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है जहां पंचायतों में डिजिटल रूप से कामकाज शुरू हो गया है। रिसर्च एंजेसी सर्विसएट नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश 57 हजार से अधिक पंचायत हैं जिसमें से 47 हजार पंचायत रेडी कैटेगरी में हैं। राज्यसभा में इन आंकड़ों की जानकारी सरकार द्वारा दी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह देश में पंचायतों के डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज योजना को अपनाने में गुजरात सबसे आगे है।

ई-ग्राम पंचायत गुजरात सबसे आगे

रिपोर्ट के अनुसार ई-ग्राम स्वराज योजना के तहत ई-ग्राम पंचायत में पहले स्थान पर गुजरात है, जहां 14621 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 9653 पंचयातों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 3877, छत्तीसगढ़ में 1651, मध्यप्रदेश में 2754 पंचायत कामकाज करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी बड़े राज्यों में ई-ग्राम पंचायतों की संख्या कम है। जिसकी बड़ी वजह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने में समस्या हो रही है। छोटे राज्यों की तुलना में बड़े राज्यों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता कम है। हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग ने ई-पंचायत की स्थापना के लिए काम शुरू कर दिया है। जिसके लिए बुनियादी व्यवस्थाओं की आपूर्ति के लिए काम शुरू कर दिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख पांच राज्य में जहां ई-ग्राम पंचायत कामकाज कर रही हैं उसमें गुजरात पहले नबंर पर है। यहां कुल ग्राम पंचायत 14621 हैं, जिसमें से 14559 ग्रांप पंचायत सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इनमें से ऑपरेशनल पंचायत लगभग 11465 हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब है जहां कुल ग्राम पंचायत 13238 है सेवाएं देने के लिए लगभग 12807 तैयार हैं, इनमें से 9432 पंचायत ऑपरेशन कर रही हैं। इस सूची में राजस्थान तीसरे स्थान पर जहां 11208 ग्राम पंचायत हैं और इनमें से सेवाएं देने के लिए तैयार 8997 पंचायते हैं, लेकिन वर्तमान में 6421 ही पंचायते ऑपरेशनल हैं। चाथे स्थान पर तेलगाना है जहां कुल ग्राम पंचायत की संख्या 12771 है इसमें सेवाओं के लिए तैयार कुल 10915 हैं लेकिन वर्तमान में केवल 5812 ही पंचायत सेवाएं दे रही हैं। पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है जहां कुल पंचायत 13326 हैं और उनमें 12967 तैयार हैं लेकिन सेवाएं 5559 पंचायतें दे रही हैं।

बडें राज्यों में ई-पंचायत की संख्या कम

बड़े राज्यों में ई-पंचायत की संख्या कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामी पंचायत 11645 हैं जिसमें से सेवाएं देने के लिए 9759 तैयार हैं लेकिन इनमें से केवल 1651 पंचायत ही काम कर रही हैं। इस सूची में मध्यप्रदेश में कुल ग्राम पंचायत 23011 में से 18105 सेवाएं देने को तैयार लेकिन 2754 ही काम कर रही हैं। तमिलनाडू में कुल ग्राम पंचायत 12525 हैं जिसमें से 9882 तैयार हैं लेकिन केवल 3449 सेवाएं दे रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है जहां कुल ग्रामी पंचायत 27911 है, इनमें से 24597 सेवाओं के लिए तैयार है और 3877 की ऑपरेशन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 57691 ग्राम पंचयात हैं जिसमें से 47341 सेवाएं देने के लिए तैयार हैं लेकिन इनमें से 3921 ही ई-ग्राम पंचायत सेवा दे रही हैं।

क्या है ई-ग्राम स्वराज योजना?

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतगत ग्रामीण इलाकों को डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाएगा। सरकार गांवों के विकास और ग्रामीणवासियों को सुविधाएं देने के ई-ग्राम स्वराज योजना में ई-पंचायत योजना शुरू की है।

बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही, स्वदेशी 4जी नेटवर्क हुआ तैयार: सिंधिया

ग्वालियर

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी का घरेलू 4जी नेटवर्क भी तैयार है और इसे 5जी में बदलने का काम चल रहा है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी तकनीक वाला 4जी नेटवर्क तैयार है और कुछ महीनों में बीएसएनएल के माध्यम से इसकी सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध होंगी।

सिंधिया ने कहा, कई लोगों ने पूछा था कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4जी नेटवर्क शुरू किया तो बीएसएनएल ने क्यों नहीं? यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प था कि अगर हमें सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करना है तो हम चीन या किसी अन्य विदेशी देश के उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी तकनीक विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिन में ग्वालियर पहुंचे और बाद में मुरैना जाकर एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत संकल्प लिया है कि भारत अपना खुद का 4जी स्टैक, कोर सिस्टम या टावर विकसित करेगा जिसे रेडिएशन एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) कहा जाता है। भारत अपनी तकनीक विकसित करेगा और देशवासियों को 4जी नेटवर्क देगा और इसमें हमें डेढ़ साल लग गए। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक रखने वाला पांचवां देश बन गया है। टावर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस नेटवर्क, सी-डॉट और टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और बीएसएनएल इसे लागू कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम अक्टूबर के अंत तक 80,000 टावर लगा देंगे और बाकी 21,000 अगले साल मार्च तक लगा देंगे। ...यानी मार्च, 2025 तक 4जी नेटवर्क के एक लाख टावर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे तेजी से डाउनलोड करने और टेलीविजन देखने में मदद मिलेगी। हम इस 4जी कोर पर 5जी का उपयोग कर सकते हैं। हमें 5जी सेवाओं के लिए टावरों में कुछ बदलाव करने होंगे और इस पर काम चल रहा है। हम जल्द ही 4जी से 5जी तक का सफर पूरा कर लेंगे। सिंधिया ने कहा कि कई ग्राहक निजी सेवा प्रदाताओं से बीएसएनएल में जा रहे हैं। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमारी सेवा तेज होगी।

कोल इंडिया की शाखा एनसीएल ने 2023-24 में सरकार को 15,000 करोड़ रुपये दिए : सीएमडी

नयी दिल्ली । कोल इंडिया की शाखा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सीएमडी बी साईराम ने शनिवार को कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में रॉयल्टी और जीएसटी के रूप में केंद्र और राज्य के खजाने में 15,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया। उन्होंने कहा कि एनसीएल ने अपने कुल कोयले का 94 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को भेजा। साईराम ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। एनसीएल के मुख्यालय में आयोजित सिंगरौली औद्योगिक शिखर सम्मेलन 2024 के मौके पर उन्होंने सिंगरौली क्षेत्र के समावेशी विकास में कंपनी के योगदान को भी रेखांकित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन आर्थिक वृद्धि, टिकाऊ औद्योगिक वृद्धि, विविधीकरण, पूर्ण औद्योगिक क्षमता का दोहन और सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। इस दौरान ऊर्जा, एल्युमीनियम, सीमेंट, रसायन और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया।

अब बैंक अकाउंट में बना सकेंगे 4 नॉमिनी, सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बैंकिंग कानून से जुड़े कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे खास है बैंक खातों के लिए 4 नॉमिनी का ऑप्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग कानून में बदलाव के बाद बैंक खातों के भी एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे। इससे अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते के पैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर या वारिस को आसानी से मिल सकेंगे। ह्क्क्ष संग समझें कि इस नियम की क्यों पड़ी जरूरत और इससे लोगों को क्या सहूलियत होगी।

क्यों पड़ी जरूरत?

मार्च के अंत तक वैसे अकाउंट की संख्या बढ़कर 78 हजार करोड़ हो गई, जिनके लिए कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब तक अकाउंट में एक ही नॉमिनी का ऑप्शन है। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में नॉमिनी की भी मौत हो जाती है तो उसके बाद क्लेम में कई परेशानियां आती हैं। सरकार अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या कम करना चाहती है।

क्या फायदा होगा?

एक से अधिक नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटेगी और परिजन को उनके पैसे मिल सकेंगे। मान लीजिए कि पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को नॉमिनी बनाया, लेकिन किसी दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। लेकिन, यदि नॉमिनी नंबर 2, 3, 4... होंगे तो इस तरह के हादसों के बाद भी दावेदार बचे रहेंगे और अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे मिल सकेंगे। इसलिए, हर अकाउंट के नॉमिनी की संख्या 4 करने पर विचार किया जा रहा है।

अभी क्या है नियम?

अभी आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी तय करने का ऑप्शन होता है। अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते में जमा पैसे को नॉमिनी को देना होता है। अभी शेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही नॉमिनी तय करने का ऑप्शन है।

कहां से आया कई नॉमिनी का आइडिया?

इंश?योरेंस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (॥स्न) अकाउंट में अभी एक से अधिक नॉमिनी तय करने की सहूलियत है। 4 नॉमिनी का आइडिया सरकार को यहीं से मिला है। बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को संसद में पेश करेंगी। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (क्क्रस्न) के लिए भी कई नॉमिनी पर विचार हो रहा है, हालांकि पूरी जानकारी संसद में विधेयक पेश होने पर ही मिल सकेगी।

अमेरिका, चीन... चिप मैन्यूफैक्चरिंग में गेम बदलेगा भारत, टाटा की सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण शुरू

नई दिल्ली: असम में टाटा की सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण कार्य की शुरुआत आज एक ब? समारोह के साथ हुई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और टाटा संस लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मौजूद रहे। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री हमेशा से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देते रहे हैं। आज असम में इस इकाई के निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी, 2024 को मंजूरी दी थी।

भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 21 दिसंबर, 2021 को 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की गई थी। जून, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साणंद, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

होगा निवेश

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टाटा की सेमीकंडक्टर यूनटि 27 हजार करो रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी। इससे 15 हजार प्रत्यक्ष और 11-13 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक बुनियादी उद्योग है। इससे विभिन्न अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

अडानी बिहार में लगाएंगे सीमेंट का प्लांट

1600 करोड़ का करेंगे निवेश

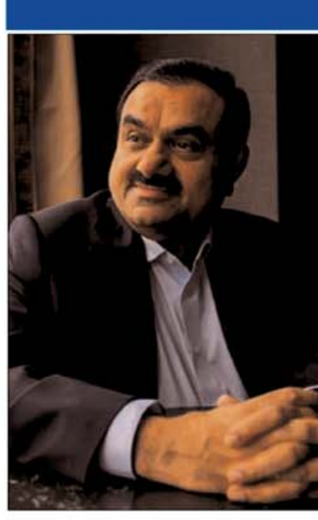

बिहार के अच्छे दिन अब जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ, केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े निवेश का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग भी बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देश के दूसरे सबसे अमीर...

बिजनेस डेस्क: बिहार के अच्छे दिन अब जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ, केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े निवेश का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग भी बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी (लड्ड्ह्वड्ड स्नड्डठ्ठ) की कंपनी ने बिहार में 1600 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। गौतम अडानी के बेटे करन अडानी ने ङ्ग पर एक पोस्ट में लिखा है कि अडानी पोर्टफोलियो की कंपनी अंबुजा सीमेंट बिहार में एक सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट लगाएगी। इस पर करीब 1600 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट किया जाएगा।

हर साल होगा सीमेंट का प्रोडक्शन

अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट बिहार के वारिसलीगंज में ये सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाएगी। इसकी कुल क्षमता 60 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) होगी। इस प्रोजेक्ट को तीन फेज में लागू किया जाएगा, जिसमें 2.4 एमटीपीए का पहला चरण 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से दिसंबर 2025 तक शुरु करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट के भविष्य के विस्तार को देखते हुए भूमि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इससे यूनिट के दूसरे चरण को बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निश्चित समय में चालू किया जा सकेगा। वारिसलीगंज एक तहसील है, जो बिहार के नवादा जिले के तहत आती है। यहां के मोसामा गांव में ये यूनिट सड़क और रेल से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। कंपनी के प्लांट से वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन 1 किमी दूर और एसएच-83 सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है।

नौवीं बार रेपो दर स्थिर रख सकता है आरबीआई; मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से, नतीजा 8 अगस्त को

बिज़नेस डायरी

विश्लेषकों के मुताबिक, आर्थिक गतिविधियों में तेजी से आरबीआई की मौजूदा स्तर पर दरें बनाए रखने की गुंजाइश आगे भी जारी रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, रेपो दरों में कमी तभी होगी, जब आरबीआई को यह विश्वास हो जाएगा कि महंगाई का दबाव कम हो रहा है, या आगे कम हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार नौवीं बार रेपो दर को यथावत रख सकता है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 6 अगस्त से शुरू होगी और 8 अगस्त को इसके निर्णय घोषित होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि हाल के महीनों में खाद्य महंगाई के ऊंचे स्तर को लेकर आरबीआई की दिक्कत बढ़ गई है। ऐसे में दरों में कमी की कोई गुंजाइश फिलहाल अक्तूबर तक नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक, आर्थिक गतिविधियों में तेजी से आरबीआई की मौजूदा स्तर पर दरें बनाए रखने की गुंजाइश आगे भी जारी रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, रेपो दरों में कमी तभी होगी, जब आरबीआई को यह विश्वास हो जाएगा कि महंगाई का दबाव कम हो रहा है, या आगे कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है। जून में खुदरा महंगाई चार महीने के उच्चतम स्तर 5.1त्न पर पहुंच गई थी। मई में यह 4.8त्न पर रही थी। इसके साथ ही महंगाई दर लगातार 57वें महीने आरबीआई के चार फीसदी के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर में अधिकांश वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति के कारण हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों और दालों की कीमतें पिछले 8 महीनों और 13 महीनों में 10त्न से ज्यादा बढ़ी है।

नीति आयोग के सदस्य विरमानी ने दिया सुझाव

आयात की जगह भारत में चीनी कंपनियों से कराया जाए निवेश

नई दिल्ली

विरमानी ने कहा कि भारत-चीन का व्यापार बंद है, लेकिन काफी कुछ आयात हो रहा है। अगर हम आने वाले 10-15 वर्षों तक कुछ सामान आयात कराने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम चीनी कंपनियों का यहां निवेश कराएं और सामान यहीं बनवाएं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का कहना है कि चीन से सामान को आयात करने की जगह अगर भारत यहां चीनी कंपनियों का निवेश कराए तो कई लाभ होंगे। इससे व्यापार बढ़ने के साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निर्यात बाजार का लाभ भी मिलेगा। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी।

विरमानी ने कहा कि भारत-चीन का व्यापार बंद है, लेकिन काफी कुछ आयात हो रहा है। अगर हम आने वाले 10-15 वर्षों तक कुछ सामान आयात कराने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम चीनी कंपनियों का यहां निवेश कराएं और सामान यहीं बनवाएं। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका और यूरोप अब चीन से आयात कम कर रहे हैं। ऐसे में भारत का चीन से सामान को आयात करने की बजाय चीनी कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे चीन द्वारा भारत में बनने वाले उत्पादों को अमेरिका और यूरोप में निर्यात करके हम काफी मजबूत बन सकते हैं।

अर्थशास्त्री विरमानी ने कहा कि हमें पहले हर समय में अच्छा देखना होगा और अच्छे समय में हर श्रेणी को देखना होगा। इसके बाद व्यापार बंद का मूल्यांकन करना होगा। उन्होंने कहा कि चीन प्लस वन रणनीति का लाभ उठाने के लिए भारत के सामने दो विकल्प हैं। एक कि भारत चीन की आपूर्ति शृंखला में शामिल हो जाए। दूसरा चीन से एफडीआई को बढ़ावा दे। इसलिए भारत को चीन से आयात जारी रखने के बाद एक समझौता करना होगा। उन्होंने कहा कि चीन से एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक जरूरी है। क्योंकि भारत चीन से सबसे ज्यादा सामान का आयात करता है और इन दिनों चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है।

भारत-चीन के बीच 2020 से संबंध तनाव पूर्ण

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है। इस विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वहीं भारत ने टिकटॉक, वी चैट और यूसी ब्राउजर जैसे 200 से अधिक चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के बड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि साल की शुरुआत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने शंघाई मुख्यालय वाली जेएसडब्ल्यू समूह के एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी।

छ.ग. श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का जिला स्तरीय बैठक संपन्न

अंबिकापुर के सर्किट हाउस में कार्यक्रम हुआ संपन्न

भारत भास्कर ब्यूरो/ अम्बिकापुर -छ.ग. श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफइकबाल व प्रदेश महासचिव बी. डी.निजामी के मार्गदर्शन में का सरगुजा जिला स्तरीय बैठक अंबिकापुर के रेस्ट हाउस में मुख्य अतिथि अखिलेश जायसवाल के उपस्थिति में संपन्न हुआ इस दौरान सर्वप्रथम अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया गया वहीं आगे के कार्यक्रम में जिला स्तरीय पत्रकार बैठक में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं पत्रकारों के हितों में और क्या विशेष किया जा सकता है इस संबंध में चर्चा की गई वहीं इस संघ के विशेष कार्य को देखते हुए लखनपुर सहित उदयपुर से पत्रकारों ने सदस्यता ली, तथा निष्क्रिय सदस्य की सदस्यता रद्द करने के संबंध में भी चर्चा की गई वही इस दौरान पत्रकारों के हित में विशेष चर्चा करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को और विस्तार रूप में लागू किए जाने हेतु आगे की कार्यवाही के संबंध में भी विशेष चर्चा किया गया है।

इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लगातार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच कर उनकी समस्याओं को लेकर के आवाज बुलंद करते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा उनके प्रति द्वेष की भावना भी रखते हैं इस पर आगे कहा कि सामने वाला कुछ भी सोचे उसे अपने आप को कोई लेना देना नहीं है मात्र अपने कार्य पर लगन से लगातार कार्य करते रहें जिस मार्ग पर चलने हेतु पत्रकार अपना वीड़ा उठाया है इस मार्ग पर आगे उनको चलते रहना है। वही इसके मान-सम्मान पर भी विशेष ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना है वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल सूरजपुर से जिला उपाध्यक्ष नंदलाल यादव एवं जिला सचिव पुनेश्वर एवं जिला उपाध्यक्ष इमरान अंसारी,महेंद्र पाल राजपूत, जिला सचिव आमोद तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश प्रसाद गुप्ता, ब्लॉक सचिव महफूज हैदर, ब्लॉक उपाध्यक्ष सीतेश सिरदार, सदस्य धर्मेंद्र कुमार झारिया सदस्य इबरार खान नए सदस्य हाशिम खान एवं जमुना प्रसाद सहित अन्य पत्रकार गण उपस्थित रहे।

आश्रम -छात्रावासों का निरीक्षण करें अधिकारी - कलेक्टर

टीएल के लंबित मामलों की गहन समीक्षा

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 05 अगस्त 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण ने आज टीएल की बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों एवं समस्याओं की जानकारी लेते हुए इनका तेजी से निराकरण करने कहा। कलेक्टर ने आश्रम और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्विलांस का काम लगातार जारी रखने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पीएचई विभाग को निर्देश दिए कि क्लोरीनेशन का काम लगातार किया जाए। 06 अगस्त को जिले में पालक शिक्षक संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। कलेक्टर ने डीएमसी समग्र शिक्षा को इसके लिए पूरी तैयारी करने कहा। उन्होंने अवैध अतिक्रमण पर भी लगातार कार्रवाई करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। कलेक्टर मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निराकृत करने कहा। कलेक्टर ने बैठक में मौसमी बीमारियों के ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।

लंबित प्रकरणों का निबटारा करने विधायक आशाराम नेताम ने नरहरपुर बैठक में दिए निर्देश

नियद नेल्लानार, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की

अशोक लुनाव/ कांकेर, विधायक आसाराम नेताम ने जनपद पंचायत नरहरपुर के सभा कक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निबटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् आवास निर्माण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो हितग्राही आवास बनवाने में रूचि नहीं ले रहे हैं उन्हें जल्द आवास बनाने के लिए प्रेरित करें, जनपद पंचायत नाहरपुर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विधायक आशाराम नेताम ने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके निराकरण के लिए उचित कार्यवाही करने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिए एवं शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, नियद नेल्लानार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, लखपति दीदी, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज, मनरेगा, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश विधायक ने दिए। इसके पहले, गैर शासकीय संगठन प्रदान द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के अभिसरण, सहभागिता तथा समन्वय से किए जाने वाले कार्यों के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष संजू लता नेताम जनपद उपाध्यक्ष संजू गोपाल साहू जनपद सदस्य राम प्रसाद सोरी सुखचंद नेतराम मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे

बेलतरा महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए विधायक सुशांत शुक्ला

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- जिले के सभी शासकीय, प्राइवेट कॉलेजों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के उद्देश्य से सोमवार को नवीन शासकीय महाविद्यालय बेलतरा में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पी लाजरस व संचालन डॉ हर्ष पांडेय ने किया।

शैक्षिक सत्र 2024-25 के नव प्रवेशित छात्रों का मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्मान कर प्रवेश उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वालित कर छात्राओं द्वारा राज्यकिय गीत व राष्ट्रगान की प्रस्तुत की गई। अतिथियों के स्वागत कर छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत गाया। तत्तपश्चात नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं का शिक्षिको के द्वारा तिलक वंदन कर मुंह मीठा कराया गया। स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य डॉ लाजरस जी ने दीक्षा आरम्भ कार्यक्रम के उद्देश्य पर व्यापक प्राकश डाला और महाविद्यालय के वस्तु स्थिति से सभी को अवगत कराया।

उद्बोधन के क्रम में मुख्य अतिथि सुशांत शुक्ला ने छात्र छात्राओं को शुभकामना देते हुए लक्ष्य बनाकर पढ़ने, नियमित रूप से विद्यालय आने और अपने शिक्षक, माता पिता के प्रति आदर भाव रखने की बात कही। उन्होंने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को युवाओं के भविष्य के लिए बहुउपयोगी बताया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन व जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षिको व भवनो की कमी के मांग पर जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए. उन्होंने कहा कि भवन की स्वीकृति पिछली बजट में प्रयास किया गया था किन्तु भवन के शासकीय भूमि अबटित नहीं हो पाई थी, हम सबको मिल कर जल्द से जल्द भवन हेतु शासकीय जमीन के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि किसी ना किसी मद से भवन की स्वीकृति कराई जा सकें, सबसे चिंता का विषय ये है की बेलतरा हाई स्कुल बिलासपुर जिले का पहला शासकीय भवन है जिसे निर्माण के 25 वर्ष भी पुरे नहीं हुआ और इस जर्जर स्थिति में पहुंच गया इस पर भी विचार करना चाहिए, उन्होंने शीघ्र ही महाविद्यालय के लिए जमीन और भवन निर्माण की बात कही।

छात्राओं ने की विधायक से शिकायत - विधायक सुशांत शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान हाई स्कुल के छात्राओं से मुलाक़ात की, छात्राओं ने शिकायत करते हुए कहा की यहां शिक्षिको की बहुत कमी है पुरे विषयो की पढ़ाई नहीं हो पाती और पढ़ाई के समय स्कुल के मैदान में बाहरी कुछ लड़के शराब पीकर लड़ाई करते है, बाइक तेज गति से मैदान में इधर उधर चलाते रहते है, इस पर उन्होंने अब ऐसा नहीं होने का आश्वासन दिए है,

कार्यक्रम में जनपद सदस्य अनीश धीवर, सरपंच ईश्वरी कौशिक, कुशल सोनी, रमेश जायसवाल, रामफल कौशिक, विनोद जायसवाल, अश्वनी जायसवाल, शीतल दास महंत, किशन जायसवाल, अश्वनी सूर्या, मुक्ता वैष्णव, श्रीमती श्रुति देव गावस्कर, नंदनी जायसवाल, नीधि तिवारी, भास्कर पटेल, प्राचार्य कावेरी यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक महाविद्यालय के विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित थे।

सार-समाचार

शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर दीक्षारंभ समारोह कार्य म में शामिल हुए विधायक आशाराम नेताम

अशोक लुनावत/कांकेर। शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर मैं दीक्षांरभ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक आशाराम नेताम ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया इस अवसर पर विधायक आसाराम नेताम ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए पढ़ाई के साथ-साथ खेल, साहित्य, एन एस, एनसीसी एवं रेडक्रॉस जैसे गतिविधियों में सहभागिता निभाने के लिए एवं पढ़ लिखकर समाज सेवा एवं देश सेवा में भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।

रेड ास सोसायटी की बैठक 6 को

भारत भास्कर/ बिलासपुर :- 05 अगस्त 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रास सोसायटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 6 अगस्त को सवेरे 11 बजे आयोजित की गई है। बैठक में वर्ष 2024-25 में नवीन आजीवन सदस्य बनाये जाने, एनुअल जनरल मीटिंग कराये जाने, जूनयिर एवं यूथ रेडक्रास हेतु प्राथमिक चिकित्सा शिविर, उद्योगो, पुलिस विभाग, ग्राम पंचायतों, भारी वाहन चालकों आदि हेतु प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जूनियर एवं यूथ रेडक्रास हेतु वार्षिक कलेण्डर, भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित रेडक्रास मेडिकल शॉप एवं जन औषधि केन्द्रों की वर्तमान स्थिति, रेडक्रास मेडिकल शॉप एवं जन औषधि में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय एवं बोनस, नवीन निर्माणाधीन सुपर मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल कोनी एवं राजकिशोर नगर में मेडिकल शॉप प्रारंभ करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन, रेडक्रास की सम्पत्तियों, रेडक्रास की वित्तिय स्थिति की जानकारी एवं रेडक्रास सोसायटी द्वारा व्यय राशि की जानकारी एवं अनुमोदन आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा सेट एवं नडेप निर्माण का किया निरीक्षण

अशोक लुनावत/कांकेर। जिले के नरहरपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आंखिहारा में कचरा सेट एवं नाडेप निर्माण का जिला पंचायत से आए अधिकारी जिला संयोजक बालमुकुंद देवांगन ने निरीक्षण किया गया। जिला संयोजक बालमुकुंद देवांगन ने पंचायत सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक को अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच सिमा कुंजाम पंचायत सचिव फिरतू कोराम, रोजगार सहायक साधना यादव सहीत पंचायत के वार्ड पंच ग्राम के कोटवाल उपस्थित रहे।

54 प्रतिशत माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास बच्चों के सवालों का फौरन कोई जवाब नहीं होताः अमेज़न एलेक्सा सर्वेक्षण

बेंगलुरु : बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और माता-पिता हमेशा ऐसे सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो। यह बात अमेज़न एलेक्सा के कांतार के ज़रिये जून 2024 को छह शहरों में 750 से अधिक अभिभावकों के बीच किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में सामने आई। इस सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 54 प्रतिशत माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास बच्चों के सवालों का फौरन कोई जवाब नहीं होता। साथ ही इसमें 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उन्हें पता न हो तो वे तुरंत सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि सर्वेक्षण में शामिल 44 प्रतिशत माता-पिता ने मौके पर ही मनगढ़ंत जवाब देने की बात स्वीकार की। सर्वेक्षण में शामिल केवल 3 प्रतिशत माता-पिता ने सवाल को अनदेखा किया या बच्चे को सवाल पूछने से रोकने के लिए विषय बदल दिया। बच्चे अक्सर कार कैसे बनाएं?, ब्रह्मांड कितना बड़ा है?, हवाई जहाज कैसे उड़ता है?, और मछली पानी के नीचे कैसे सांस लेती है?, जैसे सवाल पूछते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 60 प्रतिशत माता-पिता ने कहा कि वे अक्सर हैरान हो जाते हैं जब बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी के बीच कौन सा मौसम आता है?, माता-पिता को काम क्यों करना पड़ता है?, और हम सब्ज़ी क्यों धोते हैं? आदि। कुछ लोग जवाब देने के लिए बात अपने जीवनसाथी के ओर मोड़ देते हैं और सर्वेक्षण में शामिल 37 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अपने बच्चों से कह देते हैं कि अपनी मां से पूछ लो या अपने पिता से पूछ लो।

टीवी देखते समय बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं- इस सर्वेक्षण में बच्चों की जिज्ञासा के बारे में और विस्तार से बताया गया है; जिसमें 63त्न माता-पिता ने कहा है कि उनके बच्चे टीवी देखते समय ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं। यात्रा (57 %), पढ़ाई (56%), आउटडोर गतिविधि (55%), मोबाइल-टेबलेट जैसे डिवाइस पर कंटेंट देखना (52%), और वयस्कों के बीच होने वाले बातचीत सुनना (50त्न) उन पांच अन्य गतिविधियों में शामिल हैं जो बच्चों में जिज्ञासा जगाती हैं। इसके अलावा, भोजन, जानवर, प्रकृति, सामान्य ज्ञान, छुट्टियां, फिल्म और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे शीर्ष विषय बनकर उभरे हैं।

संक्षिप्त समाचार

तिल्दा के प्रतिष्ठित व्यापारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

रायपुर। तिल्दा के प्रतिष्ठित व्यापारी मनीष ट्रेडर्स के राहुल खूबचंदानी पिता प्रकाश खूबचंदानी के विरुद्ध रायपुर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री डी एन भगत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है । विदित हो कि राहुल खूबचंदानी की पत्नी द्वारा रायपुर न्यायालय में भरण पोषण की राशि के लिए प्रकरण पेश किया गया था जिसमे न्यायालय के आदेश के बावजूद राहुल खूबचंदानी द्वारा विगत एक साल से भरण पोषण राशि जमा नही की गई है और लगातार प्रकरण में अनुपस्थित रहते हैं न्यायालय द्वारा राहुल खूबचंदानी द्वारा एक साल से भरण पोषण राशि जमा नही करने पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

सनकी युवक ने तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा कहकर युवती को चाकू मारा

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक सनकी युवक ने प्रेमिका द्वारा बातचीत किये जाने से नाराज होकर उस पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला कबीर नगर थानाक्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सलोनी निवासी चरणदास गायकवाड़ का प्रेम संबंध कबीर नगर क्षेत्र के ग्राम अटारी की रहने वाली एक युवती से था। पिछले तीन महीने से युवती ने आरोपी प्रेमी के साथ बातचीत करना बंद कर दिया था। इस बात को लेकर युवक नाराज था तथा युवती को सबक सिखाने चाहता था। उसने युवती की हत्या करने की प्लानिंग की और प्लांनिग के तहत ही उसने युवती को 1 अगस्त शाम चार बजे अटारी आश्रम के पास मिलने के लिए बुलाया। युवती के आते ही प्रेमी ने अपने पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान युवक ने युवती से कहा कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी तथा युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां युवती की हालत नाजूक बनी हुई है। युवती के छाती, उंगली, कमर, पीठ में गंभीर चोट लगी है। मामले में कबीर नगर थाना पुलिस ने आरोपी चरणदास गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 109 बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।

सौतेल पिता की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार

रायपुर। जिले के दोकड़ा चौकी क्षेत्र में अपने सौतेल पिता की हत्या करने वाले पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप टोप्पो चैनपुर झारखंड निवासी था जो कि यहां दोकड़ी चौकी क्षेत्र के केनाडांड़ चुनदरहा में एक महिला से विवाह कर रह रहा था। महिला का पहले पति से एक पुत्र महेश राम है। जिसका अक्सर अपने सौतेली पिता प्रदीप से विवाद होता रहता था। प्रदीप अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी व सौतेल पुत्र के साथ विवाद करता था। घटना के दिन 28 जुलाई को भी प्रदीप ने शराब के नशे में अपने सौतेले बेटे-पत्नी से और शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। जिसे लेकर उनके बीच विवाद हो गया। विवाद होने पर बेटे ने डंडे से मार कर अपने पिता की हत्या कर दी।

चौधरी ने ली छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में पारिदर्शिता एवं तत्परता लाने के निर्देश

- फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश
- पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये

रायपुर/ संवाददाता

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होनें अधिकारियों से कहा स्व-प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुडे कार्यों में अपना योगदान दे। उनके द्वारा कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता हेतु प्रदेश एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश दिये गये ताकि डैश बोर्ड के माध्यम से अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा सके। श्री चौधरी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मिलने का समय भी निर्धारित कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगाने कहा। श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश दिये, जिससे कि फ्लाई

ऐश इधर-उधर न फेका जा सके। श्री चौधरी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों को प्रदान किये गये पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये तथा उद्योगों केवल वृक्षारोपण करने तक सीमित ना रहें अपितु लगाये गये पौधों के संवर्धन हेतु भी निरीक्षण का एक सिस्टम तैयार किया जाये। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वें अपने-अपने क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करायें एवं इन पेड़ों में पीपल, नीम आदि पेड़ शामिल किये जाए। श्री चौधरी ने वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हुये निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी वाहन प्रदूषण मापन प्रदूषण जाँच सिस्टम को शक्तिशाली बनाये एवं वाहन प्रदूषण मापन केन्द्रो की समय-समय पर बैठक आयोजित करें। श्री चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा में कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उठाये गये कदमों को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है तथा आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी विचार करें। उन्होनें जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री चौधरी ने परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट नियम के प्रावधानों का पालन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उद्योगों, खदानों, संस्थानों के चिमनी उत्सर्जन, परिवेशीय वायु मापन, उपचारित दूषित जल गुणवत्ता का मापन कार्य, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यकम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों, परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मापन कार्यों की भी समीक्षा की। श्री चौधरी ने कहा की शीघ्र ही सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक ली जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण सुधार कार्यों में बुद्ध जीवी वर्ग की मदद ली जायेगी। श्री चौधरी ने मंडल की पद संरचना की समीक्षा करते हुये मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुनः पदसंरचना निर्धारित करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा सभी कर्मचारियों के डेटा को एच.आर. एम.एस. सिस्टम में एक माह के भीतर अपलोड करते हुये ऑनलाईन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में मंडल की अध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सुश्री आर. शंगीता एवं मंडल के सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।

छग में अब तक 603.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 603.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 02 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1435.0 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 258.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 393.0 मिमी, बलरामपुर में 623.5 मिमी, जशपुर में 421.8 मिमी, कोरिया में 443.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 414.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 521.6 मिमी, बलौदाबाजार में 663.5 मिमी, गरियाबंद में 620.9 मिमी, महासमुंद में 465.8 मिमी, धमतरी में 641.1 मिमी, बिलासपुर में 568.2 मिमी, मुंगेली में 626.6 मिमी, रायगढ़ में 488.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 271.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 542.1 मिमी, सक्ती 444.2 कोरबा में 736.6 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 529.0 मिमी, दुर्ग में 380.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 483.9 मिमी, राजनांदगांव में 682.2 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 811.9 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 462.2 मिमी, बालोद में 758.7 मिमी, बेमेतरा में 372.0 मिमी, बस्तर में 711.6 मिमी, कोण्डागांव में 697.4 मिमी।

प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर जोरःउद्योगमंत्री लखनलाल.....

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सीएसआईडीसी की बैठक में कहा है कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 01 नवम्बर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के संचालक मण्डल की 152वीं बैठक वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्री सह अध्यक्ष सीएसआईडीसी श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में उद्योग भवन में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग श्री अंकित आनंद, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री सौरभ कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री पी. अरूण प्रसाद, वित्त विभाग के उप सचिव श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा उपस्थित थे। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। नवा रायपुर, अटल नगर सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप 141.84 एकड़ में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। पार्क की स्थापना से नवीन निवेश के साथ - साथ स्थानीय रोजगार को बढावा मिलेगा। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम गतवा, बिर्रा एवं सिलादेही में निगम के आधिपत्य की 881.60 एकड भूमि पर आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम भागोडीह, ग्राम मुक्ताराजा, ग्राम सरहर एवं ग्राम रिस्दा में निगम के आधिपत्य की भूमि में 245.29 एकड़ में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र एवं 111.02 एकड में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

बखरूपारा में आयोजित जन समस्या निवारण पखवाड़ा में प्राप्त हुए 174 आवेदन.....

- शिविर के माध्यम से वार्डवासियों को मिल रही सुविधा

रायपुर/ संवाददाता

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के तहत् आज वार्ड क्रमांक 6 और 7 के लिए क्षत्रिय समाज भवन बखरूपारा में नगर स्वराज अभियान के तहत् शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड वासियों द्वारा नगरपालिका तथा अन्य विभागों से संबंधित सेवाओं जैसे सफाई व्यवस्था, नल कनेक्शन, लोक निर्माण विभाग, पेंशन, स्वस्थ, विद्युत, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित ऋण योजनाओं, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास हेतु 174 आवेदन प्राप्त हुआ तथा साथ ही साथ नगर पालिका के करो का भुगतान हेतु शिविर में सुविधा प्रदान की जा रही है। शिविर का आयोजन 10 अगस्त तक नगर पालिका परिषद् में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के रूप में वार्डवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां स्थानीय समस्याओं का निदान किया जा जा रहा है। शिविरों में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद के पार्षदों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति से आमजनों की भागीदारी में भी वृद्धि हो रही हैं, इसके तहत् कलेक्टर श्री बिपिन मांझी द्वारा शिविर में सभी विभाग के अधिकारी को उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करने निर्देशित किया गया है। स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं जैसे नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोट-छोटे कार्य होते है, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है साथ ही नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों एवं गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गडढ़े पाटना, स्ट्रीट लाईट के मरकरी, बल्ब ट्यूब का बंद रहना आदि समस्याएं भी है। सारे कार्य आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं और कार्यों से संबंधित है। इन समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से किये जाने पर नगर पालिका के प्रति आमजन के सदभाव बढ़ेगा, वही स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का निराकरण भी शीघ्र हो रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी जल्द होगी जारी:भावना बोहरा

- गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए कारखाने से जारी की गई 12.62 करोड़ से अधिक की राशि

रायपुर/ संवाददाता

पंडरिया विधानसभा में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के बकाया भुगतान हेतु पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया द्वारा पेराई वर्ष 2023-24 में पंडरिया विधानसभा के 7500 से

अधिक शेयरधारी गन्ना किसानों से 2 नवम्बर 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक 3.13 मिट्रिक टन गन्ने की खरीदी हुई थी जिसका उचित एवं लाभकारी मूल्य के तहत (एफआरपी दर) भुगतान हेतु 91 करोड़ रुपए की राशि कारखाने द्वारा दी जानी थी। पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा लगातार किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु जल्द व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा था और वे लगातार अधिकारियों एवं प्रशासन से किसानों के भुगतान हेतु संपर्क में हैं। इसी कड़ी में आज किसानों को बकाया भुगतान हेतु 12 करोड़ 62 लाख 14 हजार 255 रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे किसानों में खुशी दिखाई दे रही है। इस राशि के साथ ही अब तक 27 फ़रवरी 2024 तक किसानों के बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। आपको बताते चले की अब तक विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से लगभग 71 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक की राशि अबतक किसानों को जारी की जा चुकी है और बकाया राशि भी जल्द ही उन्हें भुगतान कर दी जाएगी।

दीदियां हल्दी की खेती की ओर बढ़ रही आगे

रायपुर। हल्दी का उपयोग धार्मिक कार्यों के अलावा मसाला, रंग सामग्री, औषधि तथा उबटन के रूप में किया जाता रहा है। औषधि एवं घरेलू उपयोग के साथ ही हल्दी में कैंसर रोधी गुण भी पाये जाते हैं। इस क्रम में दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड कुआकोंडा के 5 ग्रामों को हल्दी की पैदावार के लिए चयन किया गया है। बिहान समूह की महिलाएं हल्दी की खेती कर आगे बढ़ती जा रही हैं। हल्दी शुभ कार्य के साथ खाने के लिए भी बेहतर उपयोग किया जाता है। हल्दी (टर्मरिक) एक भारतीय वनस्पति है यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फिट बढने वाला पौधा है जिसमें जड़ की गाठो में हल्दी मिलती है। हल्दी को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गयी है। इसके अलावा भारतीय रसोई में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज में इसको बहुत शुभ समझा जाता है विवाह में तो हल्दी की रस्म का एक विशेष महत्व है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' के तहत स्थानीय स्व सहायता समूह की दीदियों को हल्दी उत्पादन के लिए खेती की ओर आगे बढ़ रही है। समूह की महिलाएं ग्राम रेंगानार, गढ़मिरी, कुआकोण्डा, हल्बारास, मैलावाड़ा, गोगपाल के इच्छुक 50 महिलाओं को उद्यानिकी विभाग से 20 क्विंटल हल्दी बीज प्रदाय की गई है और समूह की दीदियों ने 40-40 किलो अपनी बाड़ी में हल्दी गाठों का रोपण किया है।

बस्तर क्षेत्र में हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है अमुस त्यौहार

आइए इस हरेली धरती माँ का श्रृंगार करें,एक पेड़ मां के नाम लगाएं

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपनी अति विशिष्ट परंपराओं और पर्वों के लिए जानी जाती है और हर पर्व, प्रकृति के पीछे गहरे समर्पण की मिसाल देता है। हरियाली को लेकर ऐसा ही दुर्लभ पर्व हरेली है, जब पूरी धरती हरीतिमा की चादर ओढ़ लेती है। धान के खेतों में रोपा लग जाता है और खेतों में चारों ओर प्रकृति अपने सुंदर नजारे में अपने को व्यक्त करती है। धरती माता का पूरा स्नेह पृथ्वीवासी या हर जीव-जन्तु पर उमड़ता है और इस स्नेह के प्रतिदान के लिए हम हरेली में प्रकृति को पूजते हैं। इस बार हरेली पर्व पर एक और खुशी हमारे प्रदेशवासियों के साथ जुड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने के अभियान का आगाज किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में यह अभियान पूरे उत्साह से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने हरेली के अवसर पर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। यह पेड़ वे अपनी माँ के नाम लगाएंगे साथ ही धरती माँ के नाम लगाएंगे, जो धरती हमें इतना कुछ देती है, उसके श्रृंगार के लिए पौधा लगाएंगे और सहेजेंगे। यह पौधा हमारी हरेली की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए भी यादगार होगा। साथ ही प्रदेश भर में जहां भी खुले मैदानों में पौधरोपण के आयोजन होंगे वहां लोग गेड़ी का आनंद भी लेंगे। अपनी प्रकृति और परिवेश से जुड़ने और इसे समृद्ध करने से बढ़कर सुख और क्या होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला लोक पर्व हरेली है, जो लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आस्था से परिचय कराता है। हरेली का मतलब हरियाली होता है, जो हर वर्ष सावन महीने के अमावस्या में मनाया जाता है। हरेली मुख्यतः खेती-किसानी से जुड़ा पर्व है। इस त्यौहार के पहले तक किसान अपनी फसलों की बोआई या रोपाई कर लेते हैं और इस दिन कृषि संबंधी सभी यंत्रों नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ-सफाई कर उन्हें एक स्थान पर रखकर उसकी पूजा-अर्चना करते हैं। घर में महिलाएं तरह-तरह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन खासकर गुड़ का चीला बनाती हैं। हरेली में जहाँ किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं, आपस में नारियल फेंक प्रतियोगिता करते हैं, वहीं युवा और बच्चे गेड़ी चढ़ने का मजा लेते

हैं। हरेली के दिन गांव में पशुपालन कार्य से जुड़े यादव समाज के लोग सुबह से ही सभी घरों में जाकर गाय, बैल और भैंसों को नमक और बगरंडा का पत्ता खिलाते हैं। हरेली के दिन गांव-गांव में लोहारों की पूछपरख बढ़ जाती है। इस दिन गांव के लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में कील ठोंककर आशीष देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। इसके बदले में किसान उन्हे दान स्वरूप स्वेच्छा से दाल, चावल, सब्जी और नगद राशि देते हैं। ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से बने चित्र बनाते हैं, जिससे वह उनकी रक्षा करे। हरेली त्यौहार के दिन गांव के प्रत्येक घरों में गेड़ी का निर्माण किया जाता है, मुख्य रूप से यह पुरुषों का खेल है घर में जितने युवा एवं बच्चे होते हैं उतनी ही गेड़ी बनाई जाती है। गेड़ी दौड़ का प्रारंभ हरेली से होकर भादो में तीजा पोला के समय जिस दिन बासी खाने का कार्यक्रम होता है उस दिन तक होता है। बच्चे तालाब जाते हैं स्नान करते समय गेड़ी को तालाब में छोड़ आते हैं, फिर वर्षभर गेड़ी पर नहीं चढ़ते हरेली की प्रतीक्षा करते हैं। चूंकि वर्षा के कारण गांव के कई जगहों पर कीचड़ भर जाता है, इस समय गेड़ी पर बच्चे चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं उसमें कीचड़ लग जाने का भय नहीं होता। बच्चे गेड़ी के सहारे कहीं से भी आ जा सकते हैं। गेड़ी का संबंध कीचड़ से भी है। कीचड़ में चलने पर किशोरों और युवाओं को गेड़ी का विशेष आनंद आता है। रास्ते में जितना अधिक कीचड़ होगा गेड़ी का उतना ही अधिक आनंद आता है। वर्तमान में गांव में काफी सुधार हुआ है गली और रास्तों पर काम हुआ है। अब ना कीचड़ होती है ना गलियों में दलदल। फिर भी गेड़ी छत्तीसगढ़ में अपना महत्व आज भी रखती है। गेड़ी में बच्चे जब एक साथ चलते हैं तो उनमें एक दूसरे से आगे जाने की इच्छा जागृत होती है और यही स्पर्धा बन जाती है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाते हैं और बांस के टुकड़े को बीच में फाड़कर दो भाग कर लेते हैं, फिर एक सिरे को रस्सी से बांधकर पुनः जोड़ देते हैं इसे पउवा कहा जाता है। पउवा के खुले हुए भाग को बांस में कील के ऊपर फंसाते हैं पउवा के ठीक नीचे बांस से सटाकर 4-5 इंच लंबी लकड़ी को रस्सी से इस प्रकार बांधते है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-संदीप तिवारी द्वारा अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग-मोवा रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित।
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9301031000, 0771-6556444 bharatbhaskar222@gmail.com